Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

डाक पंजीयन संख्याः-एल-2/9/रजि0/ए0डी0/119/15-17

संस्करण : लखनऊ
वर्ष : 11
अंक : 235
पृष्ठ : 6
मूल्य : 1.00

लखनऊ-मंगलवार ,23 दिसम्बर 2025

लखनऊ, प्रयागराज ,ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 सीएम की सुरक्षा में चूक, अखिलेश यादव ने जताई | 4 एडवोकेट अमर बहादुर अरावली को मृत्युदंड | 5 तारा सुतारिया की क्रिसमस पार्टी में छाया जादू

सीएम योगी ने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरूआत

वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का उद्घोष

वंदे मातरम की एक पंक्ति ने नई चेतना का संचार किया-सीएम

लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को विधानसभा में राष्ट्रगीत वंदेमातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर चर्चा की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदेमातरम स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का उद्घोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदेमातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और क्रांतिकारियों की सच्ची भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा संभवतः पहली ऐसी विधानसभा है, जहां राष्ट्रगीत वंदेमातरम पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसके लिए उन्होंने पूरे सदन का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा जब हम वंदेमातरम का स्मरण करते हैं, तो यह हमें आजादी के आंदोलन की चेतना, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। यह गीत देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम का उद्घोष करता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि वंदेमातरम आज भी हर भारतीय के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण और कर्तव्यबोध की भावना को जागृत करता है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का था, जिसके सापेक्ष अनुपूरक बजट का आकार 3.03 प्रतिशत है। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर की सलाह से कफ सिरप हर व्यक्ति लेता है। कोडीनयुक्त सिरप से मौतों के मामले अन्य राज्यों से आए हैं। यूपी में यह प्रतिबंधित है। प्रदेश में मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। यूपी में 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने भी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। अब तक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। 77 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। सीएम ने कहा कि यूपी का सबसे बड़ा स्टाकिस्ट शुभम जायसवाल, कैंट वाराणसी से सपा के प्रत्याशी अमित यादव का व्यापारिक साझेदार है। मिलिंद यादव भी शुभम का साझेदार है। सीएम ने आगे कहा कि अमित यादव और मिलिंद यादव के पत्नी के खातों से शुभम के खाते से बैंक ट्रांजेक्सन भी आए हैं। आलोक सिपाही पक्का सपाई है। अखिलेश यादव को गिफ्ट देते उसकी फोटो भी है। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कार्रवाई होगी तो आप लोग (सपा के लोग) ही फातिया पढ़ने जाएंगे। लेकिन, हम वह भी मौका नहीं देंगे।

सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया

भारत-न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर मुहर

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन से फोन पर की बात

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बेहद गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक करेगा और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा। भारत ने सोमवार को बयान में यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत संपन्न होने की सोमवार को घोषणा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की जिसके बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि नौ महीने के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का संपन्न होना

दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह मुक्त व्यापार समझौता, द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक बनाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। साथ ही यह, दोनों देशों के नवोन्मेषकों, उद्यमियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ-साथ अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड के भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने को लेकर विश्वास व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों नेताओं ने खेल, शिक्षा एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति का भी स्वागत किया। साथ ही भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सार संक्षेप

पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की बची रहेगी विधायकी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत दी। शीर्ष कोर्ट ने नासिक कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोकाटे की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। ऐसे में 30 साल पुराने मामले में मंत्री पद गंवा चुके कोकाटे के पूर्व विधायक होने का खतरा मंडराने लगा था। मराठा समुदाय से आने वाले माणिकराव कोकाटे अजित पवार की पार्टी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। कोकाटे पहले फडणवीस सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन विधानसभा में मोबाइल पर रमी खेलने के बाद विवाद खड़ा हो गया था।इसके बाद अजित पवार ने इनका विभाग बदल दिया था। कोकाटे खेल विभाग संभाल रहे थे। नासिक से आने वाले कोकाटे पांच बार के विधायक हैं।सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को दो साल की राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने नासिक कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया है।

वर्ष 2025 में रियल्टी क्षेत्र में रिकॉर्ड 10.4 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश आया: जेएलएल

नई दिल्ली। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 2025 के दौरान संस्थागत निवेश 17 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 10.4 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। जेएलएल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर प्रतिफल के लिए घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशकों ने वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं में पूंजी लगाई है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 2025 में भारतीय रियल एस्टेट में कुल संस्थागत निवेश का 52 प्रतिशत योगदान घरेलू निवेशकों का रहा। बाकी 48 प्रतिशत विदेशी कोषों से आया। आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश का अनुमान 1,040 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2024 में यह 887.8 करोड़ डॉलर था। सलाहकार ने कहा कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में कार्यालय खंड ने संस्थागत निवेश में फिर से अपना वर्चस्व कायम किया और 2025 में 58 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल की।

आरक्षण नीति विवादः

उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात, दिए कई आश्वासन

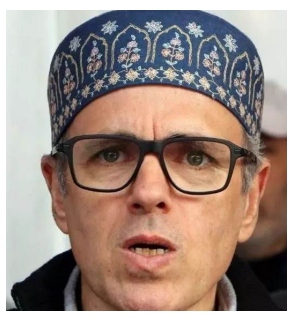

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर आरक्षण नीति के खिलाफ सोमवार को सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता रूहुल्लाह मेहदी के नेतृत्व में कई राजनीतिक नेताओं और बड़ी संख्या में छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जिसे इस साल की शुरूआत में उपराज्यपाल-प्रशासन ने द्वारा पेश किया गया था।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा श्आज मैंने ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। लोकतंत्र की खूबसूरती आपसी सहयोग की भावना से सुनने और बातचीत करने का अधिकार है। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने उनसे कुछ अनुरोध किए हैं और उन्हें कई आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा, श्संचार का यह चौनल बिना किसी बिचौलिए या पिछलग्गू के खुला रहेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने 10 दिसंबर को नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसने हाल ही में सरकार से इस पर जवाब मांगा है।मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एक छात्र प्रतिनिधि ने कहा कि 30 मिनट लंबी बैठक का मुख्य निष्कर्ष यह था कि मुख्यमंत्री ने उप-समिति को अपना काम पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा है।इससे पहले आरक्षण के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के रूहुल्लाह, वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती और अवामी इतिहाद पार्टी के नेता शेख खुर्शीद- सांसद इंजीनियर राशिद के भाई जैसे राजनीतिक विरोधी एक साथ आए थे। प्रदर्शनकारियों ने श्ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए न्यायश, श्योग्यता के लिए प्रयास करें, महानता प्राप्त करें के नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं।नेकां सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार को अपनी भर्ती नीतियों में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से न्यायसंगत दृष्टिकोण के लिए आरक्षण नीति को संशोधित करने का आग्रह किया। इससे पहले कश्मीरी अलगाववादी नेता और हुर्रियत के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक भी आरक्षण नीति पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे। हालांकि उनकी घोषणा के पांच मिनट के भीतर ही उन्हें कथित तौर पर उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। मीरवाइज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा आरक्षण के मुद्दे को जिम्मेदार लोगों द्वारा न्याय और निष्पक्षता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए न कि किसी एक समूह की कीमत पर। आरक्षण की वर्तमान स्थिति सामान्य,ओपन मेरिट श्रेणी के हितों को कम करके ऐसा करती है। उनकी चिंताओं को तुरंत दूर करने की हार्दिक अपील!

ओपनमेरिटस्टूडेंट्सएसोसिएशन का समर्थन करें। उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पहाड़ी समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। इस बदलाव ने विभिन्न श्रेणियों में कुल आरक्षित सीटों को 60 प्रतिशततक बढ़ा दिया जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल 40 प्रतिशत सीटें ही उपलब्ध रहीं। इसने ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के बीच अशांति पैदा कर दी, जो नई नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

वन भूमि अतिक्रमण पर पर बोली सुप्रीम कोर्ट- मूक दर्शक की तरह बैठी है उत्तराखंड सरकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सोमवार को उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूक दर्शक की तरह बैठे रहे और अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड सरकार और अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। न्यायालय ने कहा, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। निजी पक्षों को किसी भी प्रकार का तीसरा पक्ष बनाने से रोका जाता है और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आवासीय मकानों को छोड़कर खाली पड़ी जमीनों पर वन विभाग का कब्जा होगा। न्यायालय ने इस मामले पर अगली सुनवाई छुट्टियों के बाद तय की।

कांग्रेस ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा

मोदी सरकार ने लोगों का ट्रेन से चलना किया मुश्किल

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रेल किराये में वृद्धि को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों का ट्रेन से यात्रा करना मुश्किल बना दिया है। पार्टी प्रवक्ता अजय कुमार ने यह भी कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके रहते रेलवे की हालत खराब हो गई है। रेल मंत्रालय ने बीते रविवार को घोषणा की थी कि 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी के टिकट में प्रति किलोमीटर एक पैसा

और मेलध्एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गैर-वातानुकूलित श्रेणी व सभी ट्रेन की वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर दो पैसे की वृद्धि की जाएगी। नई दरें 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगी। कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, अश्विनी वैष्णव 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से दो बार रेल का किराया बढ़ा चुके हैं। वह इतने चतुर हैं कि यह बताते हैं हमने एक पैसा या दो पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया है, लेकिन आम जनता के ऊपर 100-200 रुपये तक का भार पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में रेलवे का किराया 107 प्रतिशत तक बढ़ चुका है तथा मोदी सरकार ने लोगों का ट्रेन से चलना भी मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, रेल मंत्री का कहना है कि किराया बढ़ाने से रेलवे को 600 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। जबकि रेलवे में खाने की थाली 120 रुपए की हो चुकी है, जो 2014 में 30 रुपये की थी।

माघ मेले को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी तैयारी, जल्द शुरू करेगा रिंग रेल सेवा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर सभी विभाग अपने अपने तरीके से लोगो को राहत देने की कवायद शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) ने दो रिंग रेल सेवा जल्द ही शुरू करने की घोषणा की है। माघ मेले के दौरान प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के बाद पूर्वोत्तर रेलवे पहली बार रिंग रेल सेवा की शुरूआत करने जा रहा है। इसका संचालन झुंसी रेलवे स्टेशन से होगा। रिंग रेल एक जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलेगी। सिटी-छपरा-थावे-सीवान-भंटनी संचालित होगी। सुबह 9.00 बजे तक झुंसी से गाड़ी संख्या 05101 की रवानगी होगी जो ज्ञानपुर रोड 10.02 बजे, माधो सिंह 10.22 बजे, बनारस 11.20 बजे, वाराणसी जं. 11.40 बजे, वाराणसी सिटी 12.05 बजे, सारनाथ 12.17 बजे, औड़िहार दोपहर 12.50 बजे, गाजीपुर सिटी 1.35 बजे, यूसुफपुर 1.55 बजे, सीवान रात 8.35 बजे, मैरवा 8.54. बजे, भाटपार रानी 9.12 बजे और रात 9.39 बजे भटनी पहुंच जाएगी। वहां से रात 10.00 बजे चलकर ट्रेन बेलथरा रोड 10.23 बजे, इंदारा 10.50 बजे, मऊ 11.15 बजे, दुल्लेहपुर 11.38 बजे, जखनियां 11.53 बजे,औड़िहार रात 12.25 बजे, सारनाथ 12.54 बजे, वाराणसी सिटी 01.20 बजे, वाराणसी 01.40 बजे, बनारस 02.00 बजे, माधो सिंह 02.35 बजे, ज्ञानपुर रोड 03.03 बजे और सुबह 4.15 बजे वापस झुंसी पहुंच जाएगी। मऊ-भटनी-सीवान-थावे-छपरा-बलिया-गाजीपुर सिटी-वाराणसी सिटी-झुंसी रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी की रवानगी झुंसी से दिन में 2.30 बजे होगी जो शाम 4.35 बजे बनारस, शाम 7: 15 बजे मऊ, रात।

मनरेगा को खत्म करने के फैसले के खिलाफ जनआंदोलन की तैयारी में कांग्रेसः जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि ग्रामीण आबादी के लिये रोजगार की गारंटी की वह शुरू से ही समर्थक रही है और यही वजह है कि उसके नेतृत्व वाली सरकार ने 1970 में महाराष्ट्र में ग्रामीणों को सूखे के संकट से उबारने के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी थी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि 1970 के दशक में भीषण सूखे के बाद, महाराष्ट्र में वी. पी. नाइक के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण संकट से निपटने के लिए अग्रणी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत की थी।उन्होंने कहा कि यह तो शुरूआत भर थी, इसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दो नयी योजनाओं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) शुरू कर दी थी। फिर 1990 के दशक की शुरूआत में, प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव-जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री भी थे ,उन्होंने देश के 100 सबसे गरीब जिलों में रोजगार आश्वासन योजना की घोषणा की।कांग्रेस नेता ने कहा ष्अप्रैल 2002 की शुरूआत में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण रोजगार से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके बाद मार्च 2004 के अंत में जारी लोकसभा चुनाव घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने का वादा किया गया।

ममता ने एसआईआर से पहले बूथ-स्तरीय सहायकों के लिए कार्यसूची की तैयार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के दौरान पार्टी के बूथ-स्तरीय सहायकों (बीएलए) को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सोमवार को विस्तृत निर्देश जारी किये। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक जन सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने चरणबद्ध कार्यसूची की रूपरेखा प्रस्तुत की और सतर्कता, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियां आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी और साथ ही जिला, उपमंडल, ब्लॉक और नगरपालिका कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाएंगी।

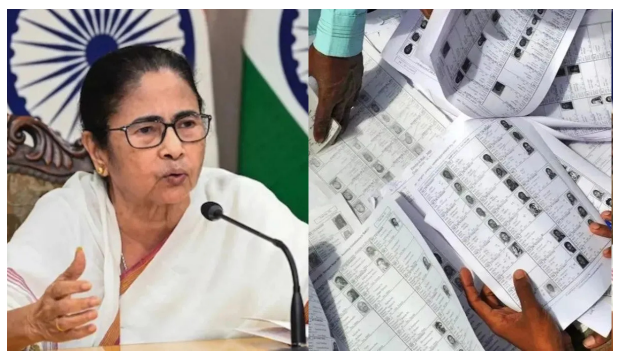

बीएलए को इन सूचियों के आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हटाए गए या अनुपस्थित के रूप में दिखाये गये कोई भी मतदाता वास्तव में दिए गए पते पर रह रहे हैं या नहीं।यदि ऐसे मतदाता पाए जाते हैं, तो बीएलए को उन्हें पुनः नामांकन के लिए फॉर्म 6 और अनुलग्नक 4 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को जमा करने में सहायता करनी चाहिए। बनर्जी ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा ष्अमान्यष के रूप में चिह्नित मतदाताओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बीएलए को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस मिल गए हों और वे 2002 की मतदाता सूची की प्रति और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ सुनवाई के लिए तैयार हों।जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, जैसा भी लागू हो) के लिए तत्काल आवेदन करने की सलाह दी। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालयों में सरकारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीएलए को बीएलओ ऐप में तार्किक विसंगतियों के रूप में चिह्नित मामलों की बारीकी से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित हों। बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को सुनवाई के दौरान अनावश्यक उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए और उनकी सहायता के लिए बूथ स्तरीय शिविरों का आह्वान किया। उन्होंने विधायकों, ब्लॉक अध्यक्षों और पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपी और चेतावनी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो कार्यहीन पार्टी नेताओं को बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कई पार्षद काम नहीं करते और पार्टी की बदनामी ही करते हैं।

मंत्र भारत

पूर्वांचल

लखनऊ-मंगलवार ,23 दिसम्बर 2025

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा, अवैध सामानों की धर-पकड़

गोरखपुर,: रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा, अवैध सामानों की धर-पकड़, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बचपन बचाओ अभियान के तहत मानव तस्करी की रोकथाम का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में 20 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वाराणसी सिटी को निगरानी के दौरान स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 1 पर 14 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला, जिसे पूछताछ के उपरान्त चाइल्ड लाइन, वाराणसी सिटी को सुपुर्द किया गया। 16 दिसम्बर, 2025 को गाड़ी सं0 15273 के स्कोर्ट द्वारा घर से भागकर जा रही एक युवती को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सीतापुर को सौंपे जाने पर उनके द्वारा वन स्टाप सेन्टर, सीतापुर को सौंपा गया। 20 दिसम्बर, 2025 को युवती के परिजन के पोस्ट पर उपस्थित होने पर युवती को वन स्टाप सेन्टर से प्राप्त कर परिजन को सुपुर्द किया गया। 18 दिसम्बर, 2025 को स्टेशन अधीक्षक, रतन सराय द्वारा रतन सराय स्टेशन पर 11 वर्ष एवं 09 वर्ष की 02 लड़कियाँ जिनके माता-पिता नही है तथा रिश्तेदारों के यहाँ रहने पर वहाँ से भगा दिये जाने के कारण लावारिस हालत में मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट थावे को सौंपा गया। 19 दिसम्बर, 2025 को पूछताछ के उपरान्त उन दोनो लड़कियों को बाल कल्याण समिति, गोपालगंज को सुपुर्द किया गया। 19 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बलरामपुर को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 15081 में 11 वर्ष की एक लड़की लावारिस हालत में मिली, जिसे उतारकर बलरामपुर पोस्ट पर लाया गया। पूछताछ के उपरान्त उक्त लड़की को चाइल्ड लाइन, बलरामपुर को सुपुर्द किया गया। 18 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बस्ती को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 02563 में 14 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला, जिसे उतारकर बस्ती पोस्ट पर लाया गया। 19 दिसम्बर, 2025 को पूछताछ के उपरान्त उक्त लड़के को चाइल्ड लाइन, बस्ती को सुपुर्द किया गया। 21 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लखनऊ जं. को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 82502 में यात्री का छूटा एक बैग मिला, जिसे लखनऊ जं. पोस्ट पर जमा कराया गया। यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त बैग सुपुर्द किया गया। 20 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोरखपुर को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 19037 में यात्री का छूटा एक बैग मिला, जिसे गोरखपुर पोस्ट पर जमा कराया गया। 21 दिसम्बर, 2025 को यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त बैग सुपुर्द किया गया। 20 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ऐशबाग को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 19715 में यात्री का छूटा एक ट्राली बैग मिला, जिसे ऐशबाग पोस्ट पर जमा कराया गया। 21 दिसम्बर, 2025 को यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त ट्राली बैग सुपुर्द किया गया। 19 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बलिया को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 11061 में महिला यात्री का छूटा एक बैग मिला, जिसे बलिया पोस्ट पर जमा कराया गया। 20 दिसम्बर, 2025 को महिला यात्री के रिस्तेदार के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त बैग सुपुर्द किया गया। 20 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भटनी को स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 1 पर यात्री का छूटा एक ट्राली बैग मिला, जिसे भटनी पोस्ट पर जमा कराया गया। यात्री के रिश्तेदार के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त ट्राली बैग सुपुर्द किया गया। 17 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट छपरा को गाड़ी सं0 22411 में यात्री का छूटा एक बैग मिला, जिसे छपरा जं. पोस्ट पर जमा कराया गया। 20 दिसम्बर, 2025 को यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त बैग सुपुर्द किया गया।

संक्षिप्त खबरें

डोर टू डोर जनसंपर्क से वार्ड 39 में बदलाव की दस्तक — जनता की पहली पसंद बन रहीं एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला

मुंबई कांदिवली पूर्व : कांदिवली पूर्व के वार्ड क्रमांक 39 में नगरसेवक पद की प्रत्याशी एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला का जनसंपर्क अभियान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। सुबह से देर शाम तक बिना थके डोर टू डोर जनसंपर्क कर वे हर गली, हर घर और हर नागरिक तक पहुँचने का संकल्प लेकर मैदान में उतरी हैं। जनता से सीधा संवाद, समस्याओं को मौके पर सुनना और उनका तत्काल समाधान निकालना—यही एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला की पहचान बन गई है। चुनाव आने से पहले ही जनसमस्याओं का अधिकतम निराकरण करना उनके कर्मठ, संवेदनशील और संघर्षशील नेतृत्व को दर्शाता है। स्थानीय नागरिकों का साफ कहना है कि एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला केवल वादों की राजनीति नहीं करतीं, बल्कि काम करके दिखाने वाली जननेत्री हैं। नाली, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने वार्ड 39 की जनता में नई ऊर्जा और विश्वास भर दिया है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यदि एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला वार्ड 39 से विजयी होती हैं, तो यह जीत सिर्फ एक प्रत्याशी की नहीं, बल्कि जनता की जीत होगी। उनकी जीत से वार्ड में वर्षों से चली आ रही समस्याओं पर निर्णायक प्रहार होगा और विकास, पारदर्शिता व जवाबदेही की नई शुरूआत होगी। आज वार्ड 39 की जनता एक स्वर में कह रही है— जो हर समय साथ खड़ी रहीं, वही हमारी सच्ची प्रतिनिधि हैं। एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला क्षेत्र की नई उम्मीद और मजबूत आवाज बनकर उभर रही हैं।

ठंड में चीनी मिल कर्मियों का धरना जारी

वाल्टरगंज। ठंड और शीतलहर के बीच गोविंद नगर चीनी मिल के गेट पर श्रमिकों एवं किसानों का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। मांगों को लेकर अड़े श्रमिक मिल परिसर के बाहर डटे हुए हैं। उनकी मांग बंद पड़ी मिल को दोबारा शुरू करना है, ताकि उन्हें फिर से रोजगार मिल सके। श्रमिकों ने प्रशासन और मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को दबाने के लिए उनका तबादला जबरन दूसरी मिलों में किया जा रहा है। नित्यराम चौधरी का कहना है कि यदि मिल नहीं चलानी है तो श्रमिकों की जमीनें वापस की जाएं और उनका बकाया वेतन का भुगतान हो। अंगद वर्मा, कमलेश पटेल, विजयपाल चौधरी, राम लखन शुक्ला, महेश पांडेय, धर्मेंद्र मौर्या, बृजेश यादव, प्रदीप चौधरी मौजूद रहे।

सर्विस लेन की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी

बस्ती। सदर ब्लॉक के ग्राम नौगढ़ से होकर गुजर रही रिंग रोड पर सर्विस लेन की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भदौरिया) गुट के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों समेत ग्रामीणों व किसानों ने रविवार को धरना जारी रखा। वक्ताओं ने कहा कि जब तक रिंग रोड पर सर्विस लेन की मांग पूरी नहीं हो जाती धरना चलता रहेगा। अध्यक्षता वीरेंद्र मौर्य ने की। प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह, राहुल पटेल सुधीर, छोटे सिंह, अवधेश यादव, अमित पांडेय, अमन पांडेय, रामधनी पांडेय, विनोद यादव, शिवदयाल यादव, राम संवारे आदि मौजूद रहे।

मंडलीय पशु आरोग्य मेला में एक हजार पशुओं की होगी जांच

बस्ती। पशुपालन विभाग की ओर से जिले में मंडल स्तरीय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी भी होगी। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिसमें सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की ओर से मंडलीय पशु आरोग्य मेला कराए जाने का फरमान आया है। इसके लिए 30 दिसंबर तिथि तय की गई है। जगह का चयन रामनगर ब्लॉक के बड़ोखर गांव में किया गया है। यहां एक हजार से अधिक पशुओं के उपचार, दवा आदि की सुविधा निशुल्क रहेगी। यहां मंडलभर के पशुपालक, पशु चिकित्सक और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बताया कि योजनाओं की उपलब्धियां और अन्य प्रकार की जानकारियां पशुपालकों को दी जाएंगी। इसकी तैयारी की जा रही है।

ओवरहाईट चार वाहनों का चालान

हरैया। पिछले दिनों नगर थाना क्षेत्र में गन्ना लदे ओवरहाईट ट्रक के पलटने से हुई दुर्घटना के बाद क्रय केंद्रों से मिल गेट तक गन्ना ले जाने वाले ट्रकों व ट्राला पर कार्रवाई जारी है। रविवार को चार वाहनों का चालान किया गया। बभनान रोड के चौराहे पर ओवर हाइट गन्ना लेकर चल रहे ट्राला व ट्रकों से लग रहे जाम व खतरे को देखते रविवार को प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने ओवरहाईट गन्ना लेकर जा रहे तीन ट्रकों व एक ट्राला का चालान काटा। वाहनों से करीब 20500 रुपये जुमार्ना लगाया।

सरकारी योजना के नाम पर ठगी

बस्ती। हरैर्या पुलिस ने सरकारी योजना का लाभ देने के नाम पर जालसाजी के मामले में कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र के बरहपुर निवासी गीता पत्नी परशुराम ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने सरकारी योजना के लाभ देने के नाम पर जालसाजी करके उनके साथ ठगी की। जानकारी होने पर जब शिकायत की तो अपशब्द कहते हुए मारापीटा। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। एसएचओ हरैर्या ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जुड़ईपुर निवासी बेचन सिंह, हुड़रा निवासी नीतू सिंह और श्याम सिंह निवासी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

सड़क हादसे में घायल सराफा व्यवसायी की मौत

परशुरामपुर। थाना क्षेत्र के गौरा पांडेय निवासी रामशंकर सोनी (42) पुत्र शिवनारायण सोनी शनिवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उन्हें अयोध्या मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रामशंकर सोनी जगन्नाथपुर बाजार में सराफा का व्यवसाय करते थे। शनिवार को वह किसी काम से अपनी कार से मनकापुर (गोंडा) गए थे। दिन में करीब 3 बजे गड़रही के पास सामने से अचानक एक कार आने से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और रामशंकर को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस उन्हें मेडिकल कॉलेज अयोध्या पहुंचाया गया। जहां हालत में सुधार न देख चिकित्सकों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया।

महेश स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के चौथे आउटलेट का शुभारंभ

लखनऊ। शहर के प्रसिद्ध मिठाई एवं खानपा न ब्रांड महेश स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ने अपने चौथे आउटलेट का शुभारंभ महानगर क्षेत्र में किया

। उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक व समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महेश स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर योगेश चावला ने बताया कि ग्राहकों के विश्वास और बढ़ती मांग को देखते हुए यह नया आउटलेट शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि महेश स्वीट्स शुद्धता, स्वच्छता और गुणवत्ता पूर्ण स्वाद के लिए जाना जाता है और महानगर स्थित नया आउटलेट भी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेगा । उद्घाटन कार्यक्रम में आए अतिथि यों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया । उपस्थित लोगों ने महेश स्ट्स के पारंपरिक स्वाद और सेवाओं की सराहना करते हुए नए आउटलेट के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुंबई महानगरपालिका : सत्ता का गणित, नेतृत्व की धार और विपक्ष का राजनीतिक अवसान

महाराष्ट्र की राजनीति अब किसी अगर मगर या अनुमान के दौर में नहीं है। नगर निकाय चुनावों से मिले संकेतों ने यह साफ कर दिया है कि अगला और सबसे निर्णायक सत्ता-संग्राम मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में समाप्त होने जा रहा है—और उसका परिणाम लगभग पूर्वनिर्धारित है। देश की आर्थिक राजधानी की यह महानगरपालिका केवल एक नगर संस्था नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी है। जो मुंबई जीतता है, वही सत्ता की दिशा तय करता है। आज की वास्तविकता यह है कि मुंबई में मुकाबला सत्ता बनाम विपक्ष का नहीं, बल्कि संगठित महायुति बनाम बिखरा हुआ भ्रम बन चुका है। बीते नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से नंबर-वन बनकर उभरना, शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट) का ठोस प्रदर्शन और कांग्रेसझ्रयूबीटी जैसे दलों का लगातार राजनीतिक संकुचन—इन सबने मिलकर यह तय कर दिया है कि तथाकथित क्ठऊक्रगठबंधन अब केवल प्रेस विज्ञप्तियों और बयानबाजी तक सीमित रह गया है। जमीन पर न उसका संगठन बचा है, न नेतृत्व और न ही विश्वसनीयता। महायुति की बढ़त किसी संयोग का परिणाम नहीं है। इसके पीछे स्पष्ट नेतृत्व, स्पष्ट दिशा और स्पष्ट निर्णय है। भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार और अमित साटम की तिकड़ी—रणनीति, संगठन और जमीनी पकड़ का ऐसा संतुलन प्रस्तुत करती है, जो मुंबई जैसे जटिल महानगर में निर्णायक सिद्ध होता है। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे का व्यावहारिक और निर्णायक नेतृत्व तथा राष्ट्रवादी से अजित पवार की प्रशासनिक पकड़—महायुति को केवल चुनावी नहीं, बल्कि शासकीय विश्वसनीयता प्रदान करती है। रामदास आठवले की सहभागिता इस गठबंधन को सामाजिक विस्तार देती है। यदि राजनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि अंकों और गणित से चलती है, तो बीएमसी का सीट-समीकरण विपक्ष की अंतिम उम्मीदों पर भी पानी फेर देता है। 227 सदस्यीय महानगरपालिका में महायुति ने जिस रणनीतिक परिपक्वता के साथ सीटों का बँटवारा किया है, उसने विपक्ष को चुनाव से पहले ही मानसिक रूप से पराजित कर दिया है। भाजपा लगभग 150 सीटों पर आक्रामक रूप से चुनाव लड़ रही है। शिवसेना (शिंदे गुट) करीब 50 सीटों पर मजबूती से मैदान में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) 27झ्र30 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, जबकि आरपीआई (आठवले) व अन्य सहयोगी दल 10झ्र15 सीटों पर। इस प्रकार महायुति 200 से अधिक सीटों पर संगठित और समन्वित ढंग से चुनाव लड़ रही है। यह केवल जीत की योजना नहीं, बल्कि वर्चस्व की घोषणा है। इसके ठीक उलट विपक्ष का हाल यह है कि न सीटों पर सहमति है, न नेतृत्व पर और न ही मुंबई के लिए कोई साझा शहरी दृष्टि। कांग्रेस और यूबीटी गुट एक-दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त हैं, जबकि मतदाता उनसे बहुत आगे निकल चुका है। यह चुनाव अब सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने का संघर्ष बन चुका है—और वह संघर्ष विपक्ष हार चुका है। मुंबई का मतदाता अब भावनात्मक नारों, डर की राजनीति या अतीत की विरासत के नाम पर वोट देने वाला नहीं रहा। आज का शहरी मतदाता चाहता है—स्थिर सरकार, तेज निर्णय, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और ठोस विकास। मेट्रो, कोस्टल रोड, झुग्गी पुनर्विकास, ट्रैफिक नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएँ और डिजिटल प्रशासन—इन मुद्दों पर जो दल सक्षम दिखता है, वही उसकी पसंद बनता है। इस कसौटी पर महायुति विपक्ष से मीलों आगे खड़ी है। बीएमसी का बजट कई राज्यों से बड़ा है। ऐसे में उसका मेयर पद केवल औपचारिक कुर्सी नहीं, बल्कि नीति और संसाधनों की कमान है। यदि यह सत्ता ऐसे गठबंधन के हाथ में जाती है, जिसके पास राज्य और केंद्र—दोनों स्तरों पर सरकार है, तो निर्णय तेज होंगे, टकराव कम होगा और विकास की रफ़्तार बढ़ेगी। विपक्ष के पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है। तथाकथित क्ठऊक्रगठबंधन का टूटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक दिशाहीनता, नेतृत्वहीनता और आपसी अविश्वास का स्वाभाविक परिणाम है। मुंबई जैसे महानगर में केवल विरोध की राजनीति नहीं चलती—यहाँ प्रबंधन, अर्थशास्त्र और प्रशासन का संयुक्त खेल होता है, जिसमें विपक्ष पूरी तरह फेल साबित हुआ है। निष्कर्ष एकदम साफ है। 16 जनवरी का फैसला केवल बीएमसी का परिणाम नहीं होगा, बल्कि वह महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की दिशा तय करेगा। मौजूदा परिस्थितियों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति की जीत लगभग सुनिश्चित है। विपक्ष का सिमटना, नेतृत्व का स्पष्ट उभार और सीटों का निर्मम गणित—इन तीनों ने सत्ता की तस्वीर अंतिम रूप दे दिया है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में यह बात अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि खुली चर्चा बन चुकी है कि 16 जनवरी को भाजपा को एक और दिवाली मिलने जा रही है—ऐसी दिवाली, जो केवल जीत की नहीं, बल्कि विपक्ष के राजनीतिक अवसान की प्रतीक होगी।

किन्नर का तीन मंजिला मकान बम से उड़ाया

चंदौली। चंदौली जिले में मोहरगंज पुलिस चौकी के पास किन्न के तीन मंजिला मकान में का तीन मंजिला मकान बीती रात अज्ञात लोगों ने बम धमाके से उड़ा दिया। देर रात करीब 12 बजे हुए इस

अचानक धमाका हुआ तो मौके पर अफरातफरी मच गई। धमाके की आवाज दूर- दूर तक सुनाई दी। चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र में मोहरगंज पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर स्थित खुशबू किन्नर विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते मकान धुएं के गुबार में घिर गया। धमाके के दौरान सो रहे थे लोग घटना के समय मकान में 12 से ज्यादा लोग सो रहे थे। अचानक हुए विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन तीन मंजिला मकान पूरी तरह धराशायी हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के घरों में भी कंपन महसूस किया गया। खुशबू किन्नर का बताया जा रहा मकान यह मकान खुशबू किन्नर का बताया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के काफी सारे किन्नर रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। पुलिस चौकी के ठीक बगल में इस तरह की बड़ी वारदात होना कानून-व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सूचना मिलते ही बलुआ थाना सहित आसपास के थानों से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। इलाके को घेराबंदी कर अपने नियंत्रण में लिया गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। जांच में जुटी पुलिस फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री के अवशेष एकत्र किए जा रहे हैं। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इस मामले में बलुआ थाना प्रभारी अतुल प्रजापति ने बताया कि घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन अवधि में निम्नवत विस्तार किया गया है

गोरखपुर,: स्टेशन पुनर्विकास के अन्तर्गत लखनऊ जं0 पर कॉनकोर्स का निर्माण हेतु प्लेटफार्म संख्या-4 एवं 5 पर किये जा रहे इंजीनियरिंग कार्य हेतु पूर्व में लिए गये ब्लॉक अवधि का विस्तार 05 जनवरी, 2026 तक किया गया है। लखनऊ जं0 के पुनर्विकास का कार्य पूरा हो जाने पर यात्रियों को उन्नत यात्री सुविधायें उपलब्ध होगी तथा परिचालनिक सुविधायें बढ़ेगी। ब्लॉक अवधि में विस्तार के फलस्वरूप गाड़ियों के टर्मिनल में परिवर्तन तथा शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन अवधि में निम्नवत विस्तार किया गया है।

टर्मिनल में परिवर्तन-

-आगरा फोर्ट से 05 जनवरी,2026 तक चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जं. इण्टरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ जं0 के स्थान पर ऐशबाग 12.25 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी तथा लखनऊ जं0 से 05 जनवरी, 2025 तक चलने वाली 12179 लखनऊ जं.-आगरा फोर्ट इण्टरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ जं0 के स्थान पर ऐशबाग से 15.55 बजे चलाई जायेगी।

-बांद्रा टर्मिनस से 27 दिसम्बर, 2025 एवं 03 जनवरी, 2026 को चलने वाली 20921 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ जं0 के स्थान पर ऐशबाग स्टेशन पर 14.20 बजे यात्रा समाप्त करेगी तथा लखनऊ जं0 से 28 दिसम्बर, 2025 एवं 04 फरवरी, 2026 को चलने वाली 20922 लखनऊ जं0-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस लखनऊ जं0 के स्थान पर ऐशबाग से 17.50 बजे चलाई जायेगी।

-पुणे से 23 एवं 30 दिसम्बर,2025 को चलने वाली 12103 पुणे-लखनऊ जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर गोमतीनगर स्टेशन पर 14.20 बजे यात्रा समाप्त करेगी तथा लखनऊ जं. से 24 एवं 31 दिसम्बर, 2025 को चलने वाली 12104 लखनऊ जं.-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर गोमतीनगर से 15.45 बजे प्रस्थान करेगी। 12103/12104 पुणे-लखनऊ-पुणे एक्सप्रेस का 02 मिनट का अस्थाई ठहराव बादशाहनगर एवं ऐशबाग स्टेशनों पर दिया जायेगा।

-पुणे से 23 एवं 30 दिसम्बर,2025 को चलने वाली 11407 पुणे-लखनऊ जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर ऐशबाग स्टेशन पर 00.50 बजे यात्रा समाप्त करेगी तथा लखनऊ जं. से 25 दिसम्बर,2025 एवं 01 जनवरी, 2026 को चलने वाली 11408 लखनऊ जं.-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर ऐशबाग से 06.30 बजे प्रस्थान करेगी।

शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन-

-गोरखपुर से 05 जनवरी, 2026 तक (मंगलवार को छोड़कर) चलने वाली 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जं-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर ऐशबाग में/से शार्ट टर्मिनेट एवं शार्ट ओरिजिनेट होगी। यह गाड़ी लखनऊ जं0 से ऐशबाग के बीच निरस्त रहेगी।

-छपरा से 04 जनवरी, 2026 तक चलने वाली 15053 छपरा-लखनऊ जं0 एक्सप्रेस लखनऊ जं0 के स्थान पर गोमतीनगर स्टेशन पर 07.40 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी गोमतीनगर से लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी।

वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये 05004/05003 गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी का संचलन गोरखपुर से 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी, 2026 को तथा झूसी से 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी, 2026 को निम्नवत किया जायेगा। 05004 गोरखपुर-झूसी माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी, 2026 को गोरखपुर से 21.30 बजे प्रस्थान कर चौरी चौरा से 22.10 बजे, गौरी बाजार से 22.26 बजे, देवरिया सदर से 23.00 बजे, भटनी से 23.28 बजे, सलेमपुर से 23.50 बजे, दूसरे दिन बेलथरा रोड से 00.15 बजे, मऊ से 01.05 बजे, औंड़िहार से 02.06 बजे, वाराणसी सिटी से 03.10 बजे, वाराणसी जं. से 03.30 बजे, बनारस से 03.50 बजे, माधो सिंह से 04.35 बजे तथा ज्ञानपुर रोड से 04.57 बजे तथा हंडिया खास से 05.27 बजे छूटकर झूसी 06.00 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 05003 झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी, 2026 को झूसी से 07.45 बजे प्रस्थान कर हंडिया खास से 08.28 बजे, ज्ञानपुर रोड से 08.51 बजे, माधो सिंह से 09.05 बजे, दूसरे दिन बनारस से 09.55 बजे, वाराणसी जं. से 10.15 बजे, वाराणसी सिटी से 11.00 बजे, औंड़िहार से 11.40 बजे, मऊ से 12.50 बजे, बेलथरा रोड से 13.31 बजे, सलेमपुर से 13.52 बजे, भटनी से 14.22 बजे, देवरिया सदर से 14.55 बजे, गौरी बाजार से 15.30 बजे, चौरी-चौरा से 15.46 छूटकर गोरखपुर 16.25 बजे पहुँचेगी।

शयनयान श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 07 कोचों सहित कुल 15 कोच लगाये जायेंगे

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये 05002/05001 गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी का संचलन गोरखपुर से 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी, 2026 को तथा झूसी से 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी, 2026 को निम्नवत किया जायेगा। 05002 गोरखपुर-झूसी माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी, 2026 को गोरखपुर से 21.30 बजे प्रस्थान कर चौरी चौरा से 22.10 बजे, गौरी बाजार से 22.26 बजे, देवरिया सदर से 23.00 बजे, भटनी से 23.28 बजे, सलेमपुर से 23.50 बजे, दूसरे दिन बेलथरा रोड से 00.15 बजे, मऊ से 01.05 बजे, औंड़िहार से 02.06 बजे, वाराणसी सिटी से 03.10 बजे, वाराणसी जं. से 03.30 बजे, बनारस से 03.50 बजे, माधो सिंह से 04.35 बजे तथा ज्ञानपुर रोड से 04.57 बजे तथा हंडिया खास से 05.27 बजे छूटकर झूसी 06.00 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 05001 झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी, 2026 को झूसी से 22.30 बजे प्रस्थान कर हंडिया खास से 23.05 बजे, ज्ञानपुर रोड से 23.25 बजे, माधो सिंह से 23.45 बजे, दूसरे दिन बनारस से 00.50 बजे, वाराणसी जं. से 01.10 बजे, वाराणसी सिटी से 01.30 बजे, औंड़िहार से 02.07 बजे, मऊ से 03.10 बजे, बेलथरा रोड से 03.52 बजे, सलेमपुर से 04.22 बजे, भटनी से 04.42 बजे, देवरिया सदर से 05.10 बजे, गौरी बाजार से 05.32 बजे, चौरी-चौरा से 05.45 बजे छूटकर गोरखपुर 06.40 बजे पहुँचेगी। इस गाड़ी में जेनरेटर सह लगेजयान का 01, एल.एस.एल.आर.डी. के 01, शयनयान श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 07 कोचों सहित कुल 15 कोच लगाये जायेंगे।

2025 ने क्रिकेट को दिए नए चैंपियन्स, इन चार टूर्नामेंट में खत्म हुआ टीमों का लंबा इंतजार

नई दिल्ली। साल 2025 में क्रिकेट को नए चैंपियन मिले। बीबीएल, आईपीएल, डब्ल्यूटीसी और महिला वनडे विश्व कप को पहली बार नए विजेता मिले। अब जबकि मौजूदा साल खत्म होने को है तो आइए जानते हैं कि किन टीमों ने खिताबी जीत का स्वाद पहली बार चखा। साल 2025 क्रिकेट की दुनिया में उस 'रीसेट बटन' की तरह रहा, जिसने कई टीमों की किस्मत पलट दी। लंबे इंतजार और अधूरे सपनों के सिलसिले को खत्म करते हुए इस साल चार अलग-अलग टूर्नामेंट्स में नए चैंपियन्स उभरे। बिग बैश लीग में हॉबार्ट हरिकेन्स (इइछ), आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (क्कछ), विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका (हळउ) और महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और पहली बार खिताब जीता। यह वो साल रहा जब मेहनत, उम्मीद और इतिहास, सबने मिलकर नए चैंपियन्स का अध्याय लिखा।

सीएम की सुरक्षा में चूक, अखिलेश यादव ने जताई चिंता, एक अधिकारी पर एक्शन

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के समय कथित तौर पर सुरक्षा में चूक होने पर नगर निगम पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला उठाते हुए आम जनता के लिए अपनी चिंता जाहिर की है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे और कार से उतरने के कुछ ही क्षण बाद एक गाय उनकी गाड़ी के पास पहुंच गई। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री की कार कार्यक्रम स्थल पर रुकी और भाजपा के स्थानीय सांसद रवि किशन सबसे पहले उतरे, उसके बाद आदित्यनाथ उतरे। मुख्यमंत्री के उतरते ही कुछ ही सेकंड में एक गाय गाड़ी की ओर दौड़ी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत घेरा बनाकर गाय को रोका और उसे भगा दिया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना की प्रारंभिक जांच में नगर निगम पर्यवेक्षक अरविंद कुमार की लापरवाही पाई गई है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया। रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ जिसके बाद घटना सामने आई। नगर आयुक्त गौरव सिंहसोगरावल ने यह पता लगाने के लिए आंतरिक जांच के आदेश दिए कि गाय ने सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ दिया।नगर आयुक्त ने कहा वीवीआईपी सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें और सख्त बनाया जाएगा। वीवीआईपी यात्राओं के दौरान मार्ग और कार्यक्रम स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। पिछले 17 दिनों में मुख्यमंत्री सुरक्षा में चूक की तीसरी घटना है। इससे पहले दो दिसंबर को वाराणसी में काशी-तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया था। चार दिसंबर को गोरखपुर हवाई अड्डे जाते समय मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान एक बस प्रतिबंधित चेतावनी क्षेत्र में घुस गई थी। सपा प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही होगी तो भाजपा राज में आम जनता की रक्षा-सुरक्षा की बात क्या ही की जाए।

योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 24496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार 24 496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करती है। सदन में बजट

प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार ही काम किया है। सरकार ने अनुपूरक बजट को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश,राजस्व लेखा का व्यय 18369.30 करोड़ और पूंजी लेखे का व्यय 6127.68 करोड़ रुपये प्रस्तावित,वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 3.03 प्रतिशत,वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये था,औद्योगिक विकास के लिए 4874 करोड़ रुपये, ऊर्जा क्षेत्र में 4521करोड़ रुपये प्रस्तावित,स्वास्थ्य क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपये और नगर विकास के लिए 1758.56 करोड़ रुपये प्रस्तावित,तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़, महिला और बाल विकास के लिए 535 करोड़ प्रस्तावित,नेडा के लिए 500 करोड़ रुपये और मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड प्रस्तावित,वित्त वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित ,उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 31 लाख 914 करोड़ आंका गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट।

विधानसभा में कोडीन कफ सिरप को लेकर सपा का हंगामा, सरकार ने कहा, यूपी में एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने कोडीन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार को लेकर हंगामा किया और अध्यक्ष के आसन के सामने आकर सरकार विरोधी नारे लगाए। वर्ष 2025 के तृतीय सत्र (शीतकालीन) की शुरूआत शुक्रवार को हुई और उस दिन सपा के दिवंगत सदस्य सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की बैठक सोमवार 11 बजे तक के लिए अध्यक्ष सतीश महाना ने स्थगित कर दी थी। सोमवार को कोडीन के मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस कफ सिरप से सैकड़ों बच्चों की जान गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इससे इंकार करते हुए दावा किया कि उप्र में इससे एक भी मौत नहीं हुई है। विधानसभा सत्र की शुरूआत में प्रश्नकाल के समय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैला है और यह बहुत दिनों से चल रहा है, डब्लूएचओ ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके सेवन से सैकड़ों बच्चों की जान गई है और हजारों करोड़ रुपये का धंधा भी हुआ है। पांडेय ने कहा इसकी जानकारी सरकार को पहले हो जानी चाहिए थी। सरकार के पास इंटेलिजेंस है, सरकार के पास खुफिया एजेंसियां हैं, इनको पहले इसकी जानकारी हो जाती और उस हिसाब से कार्रवाई की गई होती तो सैकड़ों बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है तो इस पर चर्चा करा लें और मुख्यमंत्री सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। कहा जा रहा है कि इसमें सपा के लोग हैं तो मेरी मांग है कि अगर सपा के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो दूसरे लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा उप्र में इससे एक भी मौत नहीं हुई है, ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। खन्ना ने कहा कोडीन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विपक्ष के पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। केवल नकारात्मकता फैलाना और समाज को गुमराह करना इनका एजेंडा है। इस बीच सपा के सदस्य विरोध स्वरूप अध्यक्ष के आसन के सामने आ गये और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी सदस्यों से कई बार सीट पर बैठने का अनुरोध किया। महाना ने कहा आपने (सपा) नियम 56 (सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग) के तहत नोटिस दिया है और जब उसका समय आएगा तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, आप जो तथ्य लेकर आए हैं, उस पर सरकार जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा आप हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। महाना ने कहा कि नियम 56 का समय आएगा तो सरकार जवाब देगी। ह्यह्यतब दोनों पक्षों की बात सुनकर अगर लगेगा कि चर्चा की जरूरत है तो चर्चा कराई जाएगी। महाना ने कहा ह्यह्यसंसदीय मंत्री ने कहा कि एक भी मौत कोडीन से नहीं हुई लेकिन आप कह रहे हैं कि मौत हुई है। इसके बाद उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपील की कि वे अपने स्थानों पर लौट जाएं और कार्यवाही चलने दें। तब सपा सदस्य अपनी सीटों पर चले गये।

देश में दो नमूने, एक यूपी में और दूसरा सीएम योगी के हमले के बाद भड़के अखिलेश यादव

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। सपा ने कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैला है और यह बहुत दिनों से चल रहा है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके सेवन से सैकड़ों बच्च्चों की जान गई है। जिस पर योगी ने जवाब दिया। इसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, जिनमें से एक यहां बैठते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहां वाले बबुआ भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं। सीएम के इस तीखे हमले के बाद सपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के हमले के बाद एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आत्म-स्वीकृति! किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मयार्दा की सीमा न लाँघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा।

ठंड में आने वाले फरियादियों के लिए रैनबसेरे में रुकने की कराये व्यवस्था

लखनऊ(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ह्यजनता दर्शनह्ल किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात की। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनीं और प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में भी ह्यजनता दर्शनह्ल में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन लखनऊ में होने वाले ह्यजनता दर्शनह्ल में भी बड़ी संख्या में फरियादी आते हैं। ह्यजनता दर्शनह्ल में शामिल होने के लिए एक दिन पहले रात में ही वे राजधानी पहुंच जाते हैं। यहां आने वाले फरियादी रैन बसेरों में रूकें, सरकार ने रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था की है। सीएम ने लखनऊ प्रशासन को निर्देश दिया कि रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें और रैन बसेरों में रहने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय ठंड काफी पड़ रही है। आमजन से अपील की कि पहले जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के पास पहुंचें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। हर समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान को निर्देश दिया कि प्रतिदिन जनता की समस्याएं सुनें और उनका निराकरण कराएं, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में लखनऊ न आना पड़े।ह्यजनता दर्शनह्ल में कुछ फरियादी इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनका प्रार्थना पत्र लिया और कहा कि अस्पताल से एस्टिमेट बनवाकर दीजिए। सरकार पहले दिन से ही इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार का संकल्प है कि इलाज के अभाव में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ मामले जमीन कब्जे के भी आए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूख अपनाते हुए इसकी जांच कराते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान खरीद के मामलों को लेकर पहुंचे किसानों की शिकायत सुनकर सीएम ने तत्काल संबंधित प्रशासन को समाधान के लिए निर्देशित किया। किसानों की समस्याओं का निदान ही सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में अभिभावकों के साथ बच्चे भी पहुंचे। सीएम ने बच्चों से संवाद किया, उन्हें दुलारा-पुचकारा और पढ़ाई के बारे में भी पूछा। बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के प्रश्नों का जवाब दिया, फिर सीएम ने सभी बच्चों को चॉकलेट दी और अभिभावकों से कहा कि ठंड अधिक पड़ रही है। बच्चों को ठंड में बचाकर रखें। मुख्यमंत्री का प्रेम देख अभिभावक अभिभूत हो गए।

एक देश, एक कारोबारीश का एजेंडा चला रही है भाजपाः अखिलेश यादव

लखनऊ(संवाददाता)। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर एक देश, एक कारोबारी के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसी न किसी बहाने से विभिन्न औद्योगिक घरानों को खत्म करके सभी आर्थिक गतिविधियों को अपने गिने-चुने लोगों के हाथों में देने के लिए आमादा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, एक देश, एक कारोबारी की ओर बढ़ता भाजपा सरकार का गोपनीय एजेंडा। उन्होंने इस लंबी पोस्ट में कहा, एक का धंधा, एक से चंदा, भाजपाई लोग इसी सिद्धांत के तहत देश के हर कारोबार को कुछेक लोगों के हाथों में ही समेट देना चाहते हैं। जिससे चंदे के लिए अलग-अलग जगह न जाना पड़े। अपने पैसों की महाभूख के लिए बाकी कमी को वो सरकार और भाजपा संगठन में बिना ना नुकुर के हामी भरने वाले चाबी के खिलौनों को बिठाकर पूरा करना जानते हैं। सपा प्रमुख ने कहा, किसी भी देश के लिए, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की भावना घातक साबित होती है फिर वह चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक या सामाजिक वर्चस्व का क्षेत्र। आज भाजपा सरकार जिस तरह से किसी न किसी बहाने से अन्य औद्योगिक घरानों को खत्म करके समस्त आर्थिक गतिविधियों को अपने गिने-चुने लोगों के नियंत्रण में देने के लिए आमादा है, ये कोशिश बहुत गंभीर और खतरनाक परिस्थिति को जन्म देगी, जिसका अगला कदम अनियंत्रित मुनाफाखोरी व महंगाई और अंततः महा-भ्रष्टाचार होगा। यादव ने कहा, ह्यइन्हीं एकाधिकारवादी कंपनियों के फायदे के लिए हर नियम-कानून बदला जाएगा, उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली की जाएगी। श्रमिकों का ह्यकम धन-अधिक श्रम के उत्पीड़नकारी फामूर्ले के तहत और शोषण किया जाएगा। न किसान की सुनी जाएगी न पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) समाज की मतलब 95 प्रतिशत आबादी घोर शोषण का शिकार हो जाएगी।ह्ल उन्होंने कहा, आज देश को एकजुट होकर भाजपाइयों से कहना पड़े गारू एकाधिकार, नहीं स्वीकार!

यूपी विधान परिषद में पुनर्नियोजित चिकित्सकों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग

लखनऊ(संवाददाता)। शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम-111 के अंतर्गत प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े पुनर्नियोजित चिकित्सकों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि पुनर्नियोजित चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने से प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और राज्य चिकित्सा सेवा को और अधिक गतिमान बनाने में सहायता मिलेगी। सदस्य ने कहा कि योगी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाओं के साथ-साथ अस्पतालों के उच्चीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे चिकित्सकों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सरकार ने चिकित्सकों की सेवा आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, लेकिन पुनर्नियोजित चिकित्सकों की आयु सीमा अब भी 62 से 65 वर्ष के बीच निर्धारित है। आयोग से नए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीमित उपलब्धता के कारण प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ऐसे में सेवानिवृत्त चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की आयु सीमा 70 वर्ष किए जाने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मेडिकल कॉलेजों में पहले ही पुनर्नियोजित चिकित्सकों की तैनाती की आयु सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। जब यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों में दी जा सकती है, तो राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों और सेवाओं में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की सीजीएचएस, राज्य सरकार के बीमा चिकित्सालयों और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी 70 वर्ष तक पुनर्नियोजन के उदाहरण मौजूद हैं। इसके साथ ही शून्यकाल में विधान परिषद सदस्य ने राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित निगरानी समितियों की अनियमित बैठकों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दिशा की तर्ज पर राज्य योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित इन समितियों की कुछ जनपदों में बैठकें हुई हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में अब तक नियमित बैठकें नहीं हो पाई हैं। उन्होंने इन समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित कराने की मांग की।

पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर सपा ने किया जमकर हंगामा, सरकार ने दिया ये जवाब

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को राज्य विधान परिषद में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। सपा के विधान परिषद सदस्य डॉ. मानसिंह ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर क्या कोई निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई पेंशन प्रणाली को राज्य के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के साथ-साथ न केवल सरकारी कर्मचारियों, बल्कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्य जन के लिए बेहतर, राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि एनपीएस दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे भविष्य में पेंशन दायित्वों का प्रबंधन सुचारु रूप से किया जा सके। इस पर सपा सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का भरोसा देती है। सपा सदस्यों ने मांग की कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इस मुद्दे पर सदन में कुछ समय तक चर्चा और नोकझोंक भी देखने को मिली।

संक्षिप्त खबरें

विधानसभा परिसर में सपा का प्रदर्शन,कफ सिरप घोटाले को लेकर सरकार पर लगाए आरोप

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विधान भवन के मुख्य द्वार पर समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने कोडीन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। सोमवार को सुबह 10 बजे विपक्षी सपा सदस्य हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर विधान भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। सपा के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए कोडीन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और सरकार पर कुछ लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया। सपा सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर संविधान और आरक्षण का हनन करने, मातृशक्ति के अधिकारों को कुचलने, छात्र-नौजवानों की नौकरियों में आरक्षण खत्म करने जैसे अन्य कई आरोप लगाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने पत्रकारों से कहा कि ह्यह्ययह प्रदर्शन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार विषयों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा, ह्यह्ययह कोडीन बड़ा गंभीर मामला है और इसमें हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। सरकार को शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की। सरकार के पास तमाम संसाधन थे लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने इस पर आवाज उठायी तो उसने कार्रवाई शुरू की लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। सपा के कई सदस्य अपनी पीठ पर कोडीन कफ सिरप घोटाले का पोस्टर लगाकर घूम रहे थे। सपा सदस्यों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग पर मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया। सपा सदस्य चंद्रप्रकाश लोधी ने पत्रकारों से कहा कि केवल मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कोडीन कफ सिरप पर सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी है और हम लोग आज इसके विरोध में सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। सपा सदस्य राम खिलाड़ी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप को लेकर माफिया ने 700 अवैध कंपनी बनाकर कारोबार शुरू किया लेकिन सरकार माफिया के आगे लाचार बनी हुई है।

कैसरबाग में सिल्क परिधानों की भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ

लखनऊ(संवाददाता)। क्रिसमस और नववर्ष के शुभ अवसर पर कैसरबाग स्थित ऐतिहासिक सफेद बारादरी में विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए सिल्क परिधानों की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इस प्रदर्शनी का आयोजन न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया संस्था द्वारा किया गया 4 जनवरी 25 तक चलने वाले एक्सपो भारतीय हैंडलूम संस्कृति और प्रकृति-सम्मत परिधानों का अनोखा संगम है। प्रदर्शनी में बनारसी, चंदेरी, तस्सर, कांचीपुरम, इक्कत, पैठानी, जयपुरी बगरू प्रिंट जैसे परिधान और सिल्कध्हैंडलूम मार्क वाले शुद्ध प्राकृतिक रेशों के उत्पाद मुख्य आकर्षण रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन सोमवार फैशन क्रियेटर व मॉडल दिव्या धूबी ने किया प्रदर्शनी में एम टीवी स्टार मोनिस सेविटार भी मौजूद रहे। देश के अलग-अलग राज्यों से आए बुनकरों के उत्कृष्ट सिल्क वस्त्र प्रदर्शित किए जाएंगे, जो पारंपरिक शिल्प और आधुनिक डिजाइन का अनूठा संगम होंगे। आयोजक मानस आचार्य व जावेद मकसूद ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बुनकरों को मंच प्रदान करना और लोगों को भारतीय सिल्क की समृद्ध विरासत से परिचित कराना है।

लुलु हाइपरमार्केट द्वारा आयोजित फूड फिएस्टा 2025 का भव्य समापन

लखनऊ(संवाददाता)। गोल्डी द्वारा प्रायोजित लुलु सुपर शेफ के साथ आशीर्वाद प्रस्तुत लुलु फूड फिएस्टा 2025, जिसे सनफीस्ट द्वारा पावर किया गया तथा चकदे, पिटारा, एवा और टाटा सोलफुल के सहयोग से आयोजित किया गया, अपने आखिरी दिन एक जबरदस्त और रोमांचक कुकिंग प्रतियोगिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन ने खाने और पाक-कला के शौकीनों के लिए एक शानदार मंच प्रदान किया। फूड फिएस्टा के अंतिम दिन प्रतिभागियों के बीच लाइव कुकिंग सेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता, स्वाद और प्रस्तुति से जजों व दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कड़े मुकाबले के बाद विजेताओं की घोषणा की गई, जिन्हें आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार रहेरू मानसी गुप्ता द्द विजेता (50,000-) नीलिमा शर्मा द्द प्रथम रनर-अप (30,000-) सानिया जेहराद्द द्वितीय रनर-अप (20,000-) इस प्रतियोगिता में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रतिष्ठित शेफ, संजय अग्रवाल ने जूरी जज की भूमिका निभाई। उनके अनुभव और विशेषज्ञता ने प्रतियोगिता को और भी खास बना दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनील शर्मा, जनरल मैनेजर, लुलु हाइपरमार्केट ने कहा, ह्ललुलु हाइपरमार्केट हमेशा अपने ग्राहकों और ग्राहकों को ऐसे मंच उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जहाँ वे अपनी प्रतिभा और पाक-कला कौशल को प्रदर्शित कर सकें।ह्ल शानदार प्रतिस्पर्धा, स्वाद से भरपूर व्यंजन और उत्साह से भरे माहौल के साथ लुलु फूड फिएस्टा 2025 की शानदार समाप्ति हुई।

अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां जमीनी जरूरतों से कटी हुई हैं: लोकदल

लखनऊ(संवाददाता)। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी ने अन्नपूरक बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहां है कि यह अनुपूरक बजट किसानों के लिए नहीं, बल्कि घोषणाओं और फाइलों के लिए है। किसान आज भी खाद, बिजली, पानी, भुगतान और इलाज के लिए भटक रहा है। 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सरकार आंकड़ों का ढोल पीट रही है, लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 8.08 लाख करोड़ के मूल बजट के बावजूद आज सरकार को फिर अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है, यह स्वयं स्वीकारोक्ति है कि योजनाएं सही तरीके से बनी ही नहीं। सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर, हेल्थ, नगर विकास, महिला-बाल कल्याण और गन्ना किसानों के नाम पर बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि, क्या किसानों को आज भी खाद, बिजली और गन्ना भुगतान समय पर मिल रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं और इलाज की व्यवस्था सुधरी है? क्या नगर विकास के नाम पर शहरों की बदहाल सड़कों, जलभराव और गंदगी से निजात मिली है? क्या महिला और बाल कल्याण केवल बजट पुस्तिका तक सीमित नहीं रह गया है? अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां जमीनी जरूरतों से कटी हुई हैं। जब तक बजट का लाभ आखिरी व्यक्ति, किसान, मजदूर, महिला और युवा तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसे बजट केवल कागजी अभ्यास बनकर रहेंगे। सरकार को नए बजट लाने से पहले पुराने बजट के खर्च और उसके परिणामों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जनता अब आंकड़ों से नहीं, जवाबदेही से शासन का मूल्यांकन करेगी।

संपादकीय

जानलेवा आबोहवा

देश-दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम-होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक्यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे। हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड-ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो-बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अधिक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल-रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव-सफाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है। लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए विशेष बजट की भी व्यवस्था हो। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली की तीन सौ किमी की परिधि में ग्यारह कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स हैं, जिन्हें सर्वाधिक प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। बहरहाल, दीर्घकालिक नीति बनाने व फैसलों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

आरक्षण देने में भूल हुई या बेईमानी

> शायद यही कारण था मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में कुल 7994 पद के सापेक्ष ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अनुसार लगभग 2158 पद होते हैं लेकिन ओबीसी को 1441 पद ही दिए गये। इडब्लूएस को अलग से पद देने की जगह ओबीसी की सीटों से दे दिया गया। ओबीसी की चोरी की गई 717 पदों को ईडब्ल्यूएस के रूप में दिया गया। यह बेईमानी किसी को समझ में न आए इसके लिए ईडब्ल्यूएस को 792 पद दिया गया। विचार करने वाली बात यह है कि लगभग जितनी सीट ईडब्ल्यूएस की है उसी के लगभग ओबीसी की सीटों की बेईमानी हुई है। इसकी गणितीय गणना में ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली 792 सीटों में से ओबीसी की बेईमानी की गईं 717 सीटों को घटाया जाए तो 75 सीट ही ज्यादा है। यह इसलिए भी किया गया ताकि गणितीय गुणा गणित में सीटों का अंतर पाया जाय।

देश में आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन जब उसी व्यवस्था के साथ योजनाबद्ध छेड़छाड़ होने लगे, तो यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के घ्जारी विज्ञापन में जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि अब आरक्षण की बेईमानी ही नहीं बल्कि खुलेआम डकैती की जा रही है। इसके पीछेइडब्लूएस है ?। शायद यही कारण था मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में कुल 7994 पद के सापेक्ष ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अनुसार लगभग 2158 पद होते हैं लेकिन ओबीसी को 1441 पद ही दिए गये। इडब्लूएस को अलग से पद देने की जगह ओबीसी की सीटों से दे दिया गया। ओबीसी की चोरी की गई 717 पदों को ईडब्ल्यूएस के रूप में दिया गया। यह बेईमानी किसी को समझ में न आए इसके लिए ईडब्ल्यूएस को 792 पद दिया गया। विचार करने वाली बात यह है कि लगभग जितनी सीट ईडब्ल्यूएस की है उसी के लगभग ओबीसी की सीटों की बेईमानी हुई है। इसकी गणितीय गणना में ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली 792 सीटों में से ओबीसी की बेईमानी की गईं 717 सीटों को घटाया जाए तो 75 सीट ही ज्यादा है। यह इसलिए भी किया गया ताकि गणितीय गुणा गणित में सीटों का अंतर पाया जाय। ताकि यह साबित हो सके कि ओबीसी पदों की बेईमानी नहीं की गई और न ही ईडब्ल्यूएस को ओबीसी कोटे को घटाकर दिए जाने की कोई मंसा थी। यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। उद्देश्य साफ था। ओबीसी समाज के हक को छीनकर उसे ऐसे वर्ग को देना। लेकिन इस बार बेईमानी भर्ती से पहले पकड़ी गई। सिस्टम ने यह मान लिया था कि आंकड़ों की जटिलता में यह खेल दब जाएगा, लेकिन जागरूक युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सच्चाई उजागर कर

दी। सवाल यह है कि जब संविधान स्पष्ट रूप से सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात करता है, तो फिर आर्थिक आधार पर बनाया गया ईडब्ल्यूएस कोटा ओबीसी के हिस्से को क्यों खा रहा है? पिछड़ों दलितों का भला करने का दावा करने वाले लोगों पिछड़े दलितों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर क्यों रखा गया और जब ईडब्ल्यूएस के नाम पर अलग से जनरल वर्ग को आरक्षण दे दिया तो चोरी की जरूरत क्यों पड़ गई। आज स्थिति यह है कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से पूरे सामाजिक न्याय के ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। यह आरक्षण की आत्मा पर हमला है। अगर आज ओबीसी की 700 से अधिक सीटें चुपचाप काटी जा सकती हैं, तो कल और भी अधिकार छीने जा सकते हैं। शायद यही सब कारण था की देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। यूयू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट के राय से सहमति जताई थी कि एससी-एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना इस वर्ग के गरीब लोगों से भेदभाव होगा। जस्टिस एस रविंद्र भट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिमिट को पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने अपना अल्पमत का विचार व्यक्त करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन पर असहमति जताई और उसे रद्द कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ललित ने न्यायमूर्ति भट के विचार से सहमति व्यक्त की थी। यदि ईडब्ल्यूएस में यूपीएससी वर्ग को शामिल करके आरक्षण दिया गया होता तो इस तरह की बेईमानी न होती और न ही सामाजिक द्वंद पैदा होता। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में हुई बेईमानी का पदार्फाश होते ही एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की व्यापम घोटाला कहा जाने वाला 69000 भर्ती चर्चा का विषय बन गया। यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई आगामी चार फरवरी को होनी है। 2018 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन आया था भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है परीक्षा के कुछ सवालों पर भी आपत्ति अभ्यर्थी द्वारा की जाती है। हालांकि उतना विवाद नहीं होता जितना की परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बनाई गई चयन सूची पर होता है। चयन सूची में विसंगति होने के संदेह पर आरक्षित वर्ग (पिछड़ा, दलित) के अभ्यर्थियों ने पुख्ता जानकारी जुटाया और सरकार से निवेदन किया की विसंगतियों को दूर कर उन्हें नौकरी दी जाए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ले गये। जांच पड़ताल के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया। अभ्यर्थियों का आंदोलन पूरे प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात को स्वीकार किया की ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने नौकरी देने का वादा किया और कुछ दिन बाद एक 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कराई। अपनी नौकरी को लेकर कुछ अभ्यर्थी पहले ही हाई कोर्ट पहुंच चुके थे, जब यह लिस्ट आई तो यह लिस्ट भी कोर्ट पहुंच गईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ लखनऊ की सिंगल बेंच का 13 मार्च 2023 को आदेश आता है। सिंगल बेंच के आदेश में दो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं पहला 6800 की सूची को कोर्ट रद्द कर देती है और दूसरा नए सिरे से 69000 भर्ती की लिस्ट रिव्यू करने का आदेश पारित करती है। 6800 की लिस्ट रद्द होने से उसमें शामिल अभ्यर्थी नाराज थे उन अभ्यर्थियों ने इस मामले को डबल बेंच में चौलेंज किया। डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को पूरी 69000 भर्ती की चयन सूची को नए सिरे से बनाए जाने और आरक्षण नियमों का पालन किए जाने का आदेश पारित किया। ऐसे में कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने महसूस किया कि यदि सूची नई बनाई जाएगी तो उनकी नौकरी जा सकती है क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सेवा नियम, 1981 के नियम 14 में बताए गए गुणवत्ता अंकों के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद, आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) के तहत सूची बनाने को कहा था, जिसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी जीत मान रहे। फिलहाल यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और यह पूरा प्रकरण आरक्षण से ही जुडा है।

एडवोकेट अमर बहादुर अरावली को मृत्युदंड

> पूरी दुनिया में ऐसे भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन पर्यावरण को लेकर सरकार के खौफनाक रवैये का यह अकेला उदाहरण नहीं है। नया उदाहरण 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मृत्युदंड सुनाने का है। सरकार की बनाई कमेटी की तय परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की जो अनुमति दी है, वह किसी मृत्युदंड से कम नहीं है।अगड़े-पिछड़े, लोकतांत्रिक-तानाशाही वाले तमाम देशों में पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापक बहस होती है, फिर भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारत शायद इकलौता देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर केंद्र की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी और इसमें पर्यावरणविदों की राय जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने किसी पर्यावरणविद को भले सलाहकार नहीं बनाया, फिर भी अरावली में खनन के खिलाफ जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उन पर ही सर्वोच्च न्यायाल को स्वतरू संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या गलत हो रहा है, जिस पर इतना विरोध हो रहा है।गौरतलब है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के वन विभागों और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसे अरावली को परिभाषित करने को कहा गया। कमेटी ने कोर्ट के सामने अपनी अनुशंसा में कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन चार राज्यों में लगभग 670 किमी तक फैली अरावली पहाड़ियों में वही पहाड़ियां अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जाय।

पर्यावरण संरक्षण का मोदी सरकार का वादा उसके बाकी वादों की तरह न केवल खोखला है, बल्कि डरावना भी है। इस संरक्षण के नाम पर सरकार ने एक उद्योगपति को निजी जंगल बनाकर उसमें तमाम तरह के जानवर पालने की अनुमति दे दी। पूरी दुनिया में ऐसे भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन पर्यावरण को लेकर सरकार के खौफनाक रवैये का यह अकेला उदाहरण नहीं है। नया उदाहरण 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मृत्युदंड सुनाने का है। सरकार की बनाई कमेटी की तय परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की जो अनुमति दी है, वह किसी मृत्युदंड से कम नहीं है।अगड़े-पिछड़े, लोकतांत्रिक-तानाशाही वाले तमाम देशों में पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापक बहस होती है, फिर भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारत शायद इकलौता देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर केंद्र की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी और इसमें पर्यावरणविदों की राय जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने किसी पर्यावरणविद को भले सलाहकार नहीं बनाया, फिर भी अरावली में खनन के खिलाफ जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उन पर ही सर्वोच्च न्यायाल को स्वतरू संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या गलत हो रहा है, जिस पर इतना विरोध हो रहा है।गौरतलब है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के वन विभागों और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसे अरावली को परिभाषित करने को कहा गया। कमेटी ने कोर्ट के सामने अपनी अनुशंसा में कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन चार राज्यों में लगभग 670 किमी तक फैली अरावली पहाड़ियों में वही पहाड़ियां अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जायें जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, पूरी अरावली श्रृंखला में 12,081 पहाड़ियां हैं जिनमें से मात्र 1048 पहाड़ियां ही यानी केवल 8.7 प्रतिशत हिस्सा ही सरकार के 100 मीटर के मानक पर खरी उतरता है। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 99 मीटर है, उसे भी सरकार ने पहाड़ी नहीं माना है। कमेटी की अनुशंसाओं से असहमति जताते हुए न्यायमित्र वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने इससे पहले अरावली की परिभाषा को लेकर जो नियम बनाये थे, उसके अनुसार, 3 डिग्री से अधिक ढाल, जिसमें घाटियों की चौड़ाई 500 मीटर हो, उसे अरावली श्रृंखला का हिस्सा समझा जाये, इसके अतिरिक्त पहाड़ी के नीचे (तलछटी) में 100 मीटर की चौड़ाई तक किसी भी किस्म की कोई गतिविधि ना की जाये। लेकिन अब तो नया खेल करके सौ मीटर ऊंचाई का मापदंड बना दिया गया है। जिसके बाद इन पहाड़ियों के मनचाहे खनन का खेल खेलने के लिए मैदान साफ है।कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 दिसंबर को द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में इसे श्अरावली के लिए एक डेथ वारंट यानी मृत्युदंड का ऐलान बताया था। उन्होंने लिखा था कि यह निर्णय उन समूहों के लिए वरदान है जो अवैध खनन और जमीन कब्जे में शामिल रहते हैं। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि अरावली सदियों से उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखने, थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और राजस्थान के जंगलों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब रोजमर्रा की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े जन-स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। देश के दस बड़े शहरों में सालाना 30 हजार से अधिक मौतें सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो रही हैं।दरअसल केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन कर प्राकृतिक संसाधनों के गलत तरीके से दोहन का रास्ता खोला है, ताकि कुछ उद्योगपतियों के मुनाफे की हवस पूरी हो सके। इसके बदले भाजपा को करोड़ों का चंदा मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी सत्ता बनाए रखने और मनमाने फैसले लेने में करती है। लेकिन माननीय अदालत को यह देखना चाहिए कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए न केवल करोड़ों लोगों को नुकसान में धकेला जा रहा है, बल्कि पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।

सभी का सम्मान करें, लेकिन हर व्यक्ति हर चीज पर संदेह भी रखें

> पासवर्ड ढूंढ़ने के लिए मैसेज आइकन दबाने की बजाय मैंने स्क्रीन के दाहिनी ओर मौजूद कैमरा बटन और साथ ही रिवर्स कैमरा आइकन भी दबा दिया। कैमरा तुरंत मेरे और कंधे के पीछे मौजूद उस चेहरे पर फोकस हो गया। इससे पहले कि मैं उस चेहरे का स्क्रीनशॉट ले पाता, उस अनजान व्यक्ति का भारी बैकपैक मेरे कंधे से टकराया क्योंकि बैकपैक वाला तेजी से मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया।मैं खड़ा हुआ तो मेरी सीट भी चली गई। मैं पूरे एयरपोर्ट में घूमता रहा, क्योंकि पूरा फ्लोर बस स्टैंड से भी बदतर लग रहा था। हर इंच पर यात्री थे, क्योंकि जो स्पेस एक फ्लाइट के यात्रियों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, वहां चार अलग-अलग गंतव्यों की चार फ्लाइट्स के यात्री थे। इनमें दो डिले फ्लाइट्स के यात्री थे और दो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के यात्री थे। अगले दो घंटे मैं उस चेहरे को खोजता रहा, जिसकी झलक कैमरे में दिखी थी, पर ढूंढ नहीं पाया। मुझे पता है कि स्कैमर्स अकसर अच्छे कपडे पहनते हैं और सहज तरीके से बात करते हैं। मैंने अपनी पत्नी से बात की और एहतियातन कोड वर्ड भी बदल दिया। स्कैमर्स के इस दौर में आप ज्यादा कमाने के लिए क्या सीखते हैं, यह व्यक्तिगत मसला हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन स्कैम की दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें?, यह सभी की साझा समस्या है। मुझे पता है कि स्कैमर्स अकसर अच्छे कपडे पहनते हैं और सहज तरीके से बात करते हैं। मैंने अपनी पत्नी से बात की और एहतियातन कोड वर्ड भी बदल दिया। स्कैमर्स के इस दौर में आप ज्यादा कमाने के लिए क्या सीखते हैं, यह व्यक्तिगत मसला हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन स्कैम की दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें?, यह सभी की साझा समस्या है।

एन. रघुरामन

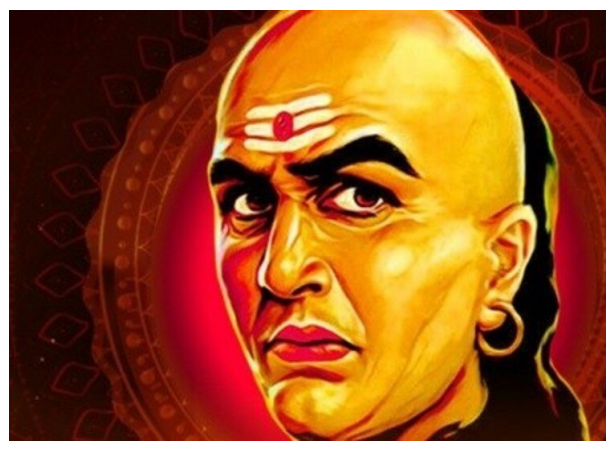

शनिवार शाम करीब 5.45 बजे मैं अनाउंसमेंट के इंतजार में जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कोने की सीट पर बैठा था। मेरी छठी इंद्री ने कहा कि मेरे कंधे के ऊपर से कोई मुझे मोबाइल पर टाइप करते देख रहा है। जैसे ही उस अनजान व्यक्ति को देखने मैं पीछे मुड़ने का सोचा कि मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आयाद्दसेंड मी द । यह मेरे और पत्नी के बीच का कोड वर्ड है, हम कभी भी पासवर्ड नहीं कहते। पासवर्ड ढूंढ़ने के लिए मैसेज आइकन दबाने की बजाय मैंने स्क्रीन के दाहिनी ओर मौजूद कैमरा बटन और साथ ही रिवर्स कैमरा आइकन भी दबा दिया। कैमरा तुरंत मेरे और कंधे के पीछे मौजूद उस चेहरे पर फोकस हो गया। इससे पहले कि मैं उस चेहरे का स्क्रीनशॉट ले पाता, उस अनजान व्यक्ति का भारी बैकपैक मेरे कंधे से टकराया क्योंकि बैकपैक वाला तेजी से मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया।मैं खड़ा हुआ तो मेरी सीट भी चली गई। मैं पूरे एयरपोर्ट में घूमता रहा, क्योंकि पूरा फ्लोर बस स्टैंड से भी बदतर लग रहा था। हर इंच पर यात्री थे, क्योंकि जो स्पेस एक फ्लाइट के यात्रियों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, वहां चार अलग-अलग गंतव्यों की चार फ्लाइट्स के यात्री थे। इनमें दो डिले फ्लाइट्स के यात्री थे और दो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के यात्री थे। अगले दो घंटे मैं उस चेहरे को खोजता रहा, जिसकी झलक कैमरे में दिखी थी, पर ढूंढ नहीं पाया। मुझे पता है कि स्कैमर्स अकसर अच्छे

कपडे पहनते हैं और सहज तरीके से बात करते हैं। मैंने अपनी पत्नी से बात की और एहतियातन कोड वर्ड भी बदल दिया। स्कैमर्स के इस दौर में आप ज्यादा कमाने के लिए क्या सीखते हैं, यह व्यक्तिगत मसला हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन स्कैम की दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें?, यह सभी की साझा समस्या है। एक परिवार के तौर पर बरती जाने वाली सावधानियां यहां पेश हैं। व्हाट्सएप घोस्टपेयरिंग साइबर फ्रॉड का नया तरीका है। इसमें ठग व्हाट्सएप के मल्टी-डिवाइस पेयरिंग फीचर का दुरुपयोग करता है। ठग, यूजर्स को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बहकाते हैं, जो अकसर कस्टमर सपोर्ट वेरिफिकेशन, नौकरी, सर्वे के नाम पर भेजे जाते हैं। स्कैन करते ही ठग का डिवाइस पीड़ित के व्हाट्सएप से ह्यलिंक्डह्ण हो जाता है। फिर स्कैमर आपकी पहचान बनकर दूसरों से बात कर सकता है। सुरक्षित रहने के लिए अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें। लिंक्ड डिवाइसेज की नियमित जांच करते रहें। स्कैमर्स घबराहट और जल्दबाजी पैदा करके फंसाते हैं। मसलन, कोई टोल नाका क्रॉस करते ही वे ट्रैफिक चालान भेज देंगे। लिंक पर क्लिक करने को कहेंगे। पर क्लिक न करें। डर या दबाव लगे तो एक पल रुकें और सोचें। अकसर पहला ट्रैप यही होता है। कभी भी सार्वजनिक जगहों पर अनजान केबल या चार्जिंग पोर्ट से फोन चार्ज न करें। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेकर दूसरे डिवाइस में सुरक्षित रखना भी कारगर है। ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड कभी नोट्स ऐप, स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप चौट में न रखें। ये साइबर अपराधियों को खुला न्योता है। सार्वजनिक वाई-फाई के इस्तेमाल से बचें। संदिग्ध फोन कॉल पर फैमिली विशेष कोड वर्ड यूज करें। सभी जरूरी अकाउंट्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखना चाहिए। संभव हो तो बैंक अकाउंट से जुडे फोन नंबर को रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले नंबर अलग रखें, ताकि हैकिंग को रोक सकें। सामान्य नियम यह है कि अनजान नंबर से आए मैसेज या फाइल पर इंटरैक्ट न करें। लिंक पर क्लिक और अटैचमेंट को डाउनलोड न करें, चाहे कितना ही असली लगे।

एशिया कप जीत पर पाकिस्तान में क्यों मन रहा बेतहाशा जश्न

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। उनकी इस जीत का जश्न पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है जैसे टीम ने अंडर-19 एशिया कप नहीं विश्व कप ट्रॉफी जीत ली है। सोशल मीडिया पर यूजर्स पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। समीर मिन्हास की शतकीय पारी की मदद से पाकिस्तान ने रविवार को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान की खिताबी जीत का जश्न पूरे पाकिस्तान में मना। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें देखा जा सकता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की टीम बस का ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया गया। उन पर फूल फेंके गए। सोशल मीडिया पर अब यूजर्स पाकिस्तान को इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि 'जश्न तो ऐसे मना रहे हैं जैसे विश्व कप जीत लिया है।'

तारा सुतारिया की क्रिसमस पार्टी में छाया जादू

घर की सजावट बनी सबकी पसंद

एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने हाल ही में अपने घर पर एक शानदार प्री-क्रिसमस पार्टी होस्ट की। उनकी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उनके घर की सजावट से प्रेरणा ले रहे हैं। अगर आप भी इस साल अपने घर को मैजिकल विंटर वंडरलैंड जैसा बनाना चाहते हैं, तो तारा के डेकोर आइडियाज आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे।

पार्टी का खास आकर्षण

दिसंबर के आखिरी सप्ताह में क्रिसमस पार्टी करना आम बात है, लेकिन इस बार तारा की पार्टी ने सबका ध्यान खींचा। सिर्फ फिल्मी सितारों की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उनके घर की सजावट ने भी सभी का दिल जीत लिया। घर को तारा ने परियों की कहानी जैसा सजाया था जहां चारों तरफ जगमगाती रोशनी, फूल और फेस्टिव डेकोर नजर आ रहा था।

डेकोर में सादगी के साथ रॉयल टच

तारा ने सजावट में सादगी के साथ रॉयल्टी का तड़का लगाया। चमकते झूमर, ढेरों मोमबत्तियां और खास तरीके से सजाई गई डाइनिंग टेबल ने पार्टी को और खूबसूरत बना दिया। तारा ने खुद बताया कि उन्होंने इस सजावट और खाने के लिए काफी मेहनत की थी।

वार्म और ड्रीमय लाइटिंग

तारा की सजावट की सबसे बड़ी खासियत थी लाइटिंग। उन्होंने घर में सिर्फ चमकदार लाइट्स का ही नहीं, बल्कि वार्म ग्लो देने वाली रोशनी का इस्तेमाल किया। आप भी अपने घर के कोनों में झूमर, फेयरी लाइट्स और मोमबत्तियां लगाकर इसी तरह का कोजी और जादुई एहसास दे सकते हैं।

लाल फूलों का क्लासिक टच

क्रिसमस सजावट में लाल और हरा रंग बहुत खास होते हैं। तारा ने अपने घर में ताजे लाल फूल जैसे गुलाब और पॉइन्सेटिया का इस्तेमाल किया। डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल पर ये फूल साधारण कमरे को भी रॉयल लुक दे देते हैं।

विंटेज क्रॉकरी और टेबल सेटिंग

पार्टी की खासियत में विंटेज क्रॉकरी भी शामिल थी। तारा ने देश भर से खास प्लेट्स, चम्मच और ग्लास इकट्ठा किए। डाइनिंग टेबल पर सुंदर कपड़ा बिछाकर छोटे सजावटी सामान रखने से टेबल सेटिंग और भी आकर्षक लगती है।

ट्रेडिशनल क्रिसमस ट्री

क्रिसमस ट्री के बिना सजावट अधूरी होती है। तारा ने बड़े और घने क्रिसमस ट्री लगाए, जिन्हें छोटे-छोटे ऑनामेंट्स, रिबन और लाइट्स से सजाया गया। लिविंग रूम के एक कोने में ट्री सजाकर उसके नीचे गिफ्ट बॉक्स रखने से डेकोर पूरा हुआ।

लग्नाजिता चक्रवर्ती कौन हैं? मां दुर्गा गीत विवाद के बाद चर्चा में आईं ये सिंगर, 1 गाने ने रातोंरात बनी थी स्टार

पश्चिम बंगाल के एक निजी स्कूल में आयोजित एक साधारण सा संगीत कार्यक्रम अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं मशहूर बंगाली सिंगर लग्नाजिता चक्रवर्ती, जिनका मां दुर्गा का गीत गाना अचानक विवाद का कारण बन गया। घटना के मुताबिक, लग्नाजिता चक्रवर्ती स्कूल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही थीं। शो की शुरूआत के करीब 45 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सातवां गीत ह्यजागो मांह्ल गाना शुरू किया, तभी स्कूल के मालिक महबूब मलिक मंच पर आ गए और उन्हें यह गीत गाने से रोक दिया। सिंगर का आरोप है कि मंच पर उनके साथ बदतमीजी, अभद्र भाषा और धक्का-मुक्की की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अगर वहां मौजूद लोग बीच में नहीं आते, तो मामला हाथापाई तक पहुंच सकता था। इसके बाद लग्नाजिता ने मंच से ही ऐलान किया कि वह आगे परफॉर्म नहीं करेंगी और शो बीच में ही छोड़ दिया। घटना के बाद लग्नाजिता चक्रवर्ती ने स्कूल मालिक महबूब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि मां दुर्गा का गीत गाने पर उनके खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई। बता दें की शनिवार शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। लग्नाजिता चक्रवर्ती बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी और लोकप्रिय सिंगर हैं। उन्हें असली पहचान बंगाली सुपरहिट गीत ह्यबसंतो एशे गेछेह्ल के फीमेल वर्जन से मिली थी, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन, साल 2015 में शेरा बंगाली अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य से बाहर परफॉर्म करने वाली सबसे कम उम्र की बंगाली सिंगर है। करियर की शुरूआत गीत ह्योदल-बोदलह्ल से की। लग्नाजिता चक्रवर्ती ने सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने बंगाली फिल्म ह्योजोदी बोलों हांह्ल में अभिनय किया। हालांकि उनके अभिनय को सराहना मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। साल 2014 में फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और लगातार एक सिंगर के रूप में ही अपने फैंस से जुड़ी रहीं। लग्नाजिता चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह इंस्टाग्राम के जरिए अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, लाइव शोज और निजी पलों की झलक फैंस के साथ साझा करती रहती हैं।

धर्मेंद्र, शेफाली जरीवाला के अलावा इन सितारों के जाने से भी रोया पूरा देश

2025 के दौरान बॉलीवुड ने धर्मेंद्र, असरानी, मनोज कुमार और पंकज धीर जैसे कई जाने-माने नाम खो दिए, जिनकी प्रतिभा ने सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी। हर मौत अपने पीछे यादें, मील के पत्थर और एक खालीपन छोड़ गई। जैसे ही 2025 में पर्दा गिरने वाला है, इंडस्ट्री उन लोगों को याद करने के लिए रुकती है जिन्होंने आखिरी विदाई ली।

धर्मेंद्र के जाने से रोया पूरा देश

नवंबर 2025 एक मुश्किल समय था। नवंबर की शुरूआत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की चिंता से हुई। हफ्तों बाद, यह चिंता देओल परिवार के लिए दुख में बदल गई। बॉलीवुड के ओरिजिनल ही-मैन, धर्मेंद्र, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने एक युग को परिभाषित किया का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय सिनेमा में एक उल्लेखनीय अध्याय का अंत कर दिया।

सुलक्षणा पंडित ने भी दुनिया को कहा-अलविदा

धर्मेंद्र की मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले, एक और चौंकाने वाला नुकसान हुआ था। विनोद खन्ना, शशि कपूर और राजेश खन्ना जैसे नामों के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए जानी जाने वाली, दिग्गज अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का 7 नवंबर को निधन हो गया। दोनों सितारों के जाने से नवंबर सामूहिक शोक का समय बन गया।

पंकज धीर और सतीश शाह के निधन से लगा गहरा झटका

अक्टूबर 2025 में भी आंसू थे। इंडस्ट्री ने हिंदी टेलीविजन के कर्ण पंकज धीर और सतीश शाह को अलविदा कहा, जिन्होंने कल्ट सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई में प्यारे इंद्रावर्धन साराभाई का किरदार निभाया था। 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को उनकी मृत्यु ने नुकसान के एहसास को और गहरा कर दिया।

जुबीन गर्ग की मौत से हिली दुनिया

सितंबर 2025 ने दिल टूटने का दर्द और बढ़ा दिया। सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की अचानक मौत इंडस्ट्री और देश भर में उनके प्रशंसकों के लिए एक झटका थी। अपनी दमदार आवाज और हिंदी, बंगाली और असमिया संगीत में अपने काम के लिए जाने जाने वाले जुबीन का 19 सितंबर को 52 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु ने एक ऐसी खामोशी छोड़ दी जो संगीत की दुनिया से कहीं ज्यादा महसूस की गई।

शेफाली जरीवाला ने रूलाया पूरा देश

जून 2025 ने सभी को चौंका दिया। 27 जून की सुबह अविश्वास के साथ शुरू हुई क्योंकि शेफाली जरीवाला की

पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहररू मास्टर सलीम के पिता का निधन

प्रसिद्ध पंजाबी गायक मास्टर सलीम के पिता पूरन शाह कोटी का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे पंजाबी संगीत और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हंस राज हंस सहित कई प्रमुख हस्तियां मास्टर सलीम से मिलकर दुख व्यक्त करने पहुंचीं। पूरन शाह कोटी पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही कलाकारों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों में गहरा दुख देखा गया।

संगीत के प्रति योगदान और प्रेरणा

बताया जाता है कि पूरन शाह कोटी ने अपने बेटे मास्टर सलीम को बचपन से ही संगीत के प्रति प्रेरित किया। हर कठिन दौर में उन्होंने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। मास्टर सलीम कई मंचों पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रहा है।

कलाकारों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

निधन की सूचना मिलते ही पंजाबी संगीत जगत के कई नामी कलाकारों, संगीतकारों और सामाजिक हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा किए। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशंसकों ने भी मास्टर सलीम के साथ दुख साझा करते हुए उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की कामना की।

हंस राज हंस ने जताया शोक

पूर्व सांसद एवं प्रसिद्ध गायक हंस राज हंस मास्टर सलीम के निवास स्थान पहुंचे और परिवार से मिलकर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूरन शाह कोटी एक सादगीपूर्ण और सम्मानित व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जाना न केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरे कला जगत के लिए भी बड़ी क्षति है। पूरन शाह कोटी का जाना पंजाबी संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके द्वारा बेटे को दी गई प्रेरणा और आशीर्वाद हमेशा याद रहेंगे।

बिग बॉस 19 में नीलम गिरि का लेटर फाड़ने पर फरहाना भट्ट ने दी प्रतिक्रिया, बोलीं- सब ओवरएक्टिंग कर रहे थे

बिग बॉस 19 में दूसरे नंबर पर रहीं फरहाना भट्ट के खेल को काफी पसंद किया गया। अब फरहाना ने बिग बॉस के उस चर्चित घटनाक्रम के बारे में बताया जहां उन्होंने नीलम गिरि के लेटर को फाड़ दिया था। जानिए फरहाना ने क्या कुछ बताया फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनर अप रही थीं। फाइनल में उन्हें गौरव खन्ना से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बिग बॉस के पूरा होने के बाद फरहाना कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में नजर आईं। यहां फरहाना ने बिग बॉस के अपने सफर के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान फरहाना ने बिग बॉस के घर में हुई उस घटना के बारे में भी बताया, जहां उन्होंने साथी कंटेस्टेंट नीलम गिरि का लेटर फाड़ दिया था। इसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। फरहाना बोलीं- मैं सही थी वीडियो व्लॉग के दौरान फराह खान ने फरहाना से उस खास एपिसोड के बारे में बात की। इस दौरान फराह ने पूछा कि जब नीलम गिरि का लेटर फाड़ देने पर घर के बाकी लोगों ने उनकी आलोचना की थी, लेकिन उस वक्त भी वो काफी शांत रही थीं। इस पर फरहाना ने कहा कि मैं शांत थी। सब लोग इतना ओवरएक्टिंग कर रहे थे और मुझे मजा आ रहा था। इतना अच्छा दिखने के लिए कोई ऐसा कर सकता था? वो मुझे ट्रिगर नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसलिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं शांत रही।

विवादों के बीच शिल्पा शेट्टी ने साझा की पिता के साथ तस्वीर

85वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुई अभिनेत्री

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम इन दिनों विवादों में छाया हुआ है। इसी बीच सोमवार को अपने पिता की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवंगत पिता की 85वीं जयंती के मौके पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा कर उन्हें याद किया। इस खास दिन पर शिल्पा ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें पिता-बेटी के बीच का गहरा रिश्ता साफ झलकता है। इन तस्वीरों ने न सिर्फ शिल्पा की निजी भावनाओं को सामने रखा, बल्कि उनके परिवार की एकजुटता और प्यार की झलक भी दिखाई। शिल्पा ने पिता के साथ साझा की तस्वीरें शिल्पा द्वारा साझा की गई तस्वीरों में उनके पिता के साथ बिताए गए खास पल कैद हैं। एक तस्वीर में उनके पिता अपने नाती वियान के साथ नजर आते हैं, जो परिवार के तीन पीढ़ियों के रिश्ते को खूबसूरती से दशार्ती है। इसके अलावा एक ग्रुप फोटो में शिल्पा और उनकी बहन शमिता शेट्टी अपने पिता के साथ दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए शिल्पा ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा कि वह उम्मीद करती हैं कि पिता जहां भी हों, वहां अपनी पसंदीदा ड्रिंक के साथ इस दिन का जश्न मना रहे होंगे। शिल्पा के पिता का निधन शिल्पा और शमिता के पिता का निधन अक्टूबर 2016 में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। उनके जाने के बाद भी शिल्पा अक्सर उन्हें याद करती रही हैं और खास मौकों पर अपने जज्बात सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करती हैं। पिता के प्रति उनका यह प्यार और सम्मान फैंस के दिलों को भी छू गया। शिल्पा ने राज अपनी बात रखी। शिल्पा ने साफ कहा कि जिस कंपनी से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, उसमें उनकी भूमिका केवल पेशेवर एंडोर्समेंट तक सीमित थी और उनका कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज या फैसलों से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके परिवार ने उस कंपनी को बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी थी, जो अब तक वापस नहीं मिली है। शिल्पा के अनुसार, इतने वर्षों बाद उनके नाम को इस तरह किसी मामले में घसीटना न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

डेब्यू मैच में विकेट नहीं मिलने के बाद क्या बोलीं वेष्णवी शर्मा

विशाखापत्तनम। वैष्णवी ने कहा कि टीम प्रबंधन और सीनियर खिलाड़ियों विशेष रूप से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनका हौसला बनाए रखा। भारत की बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने कहा कि महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में विकेट नहीं मिलने के बावजूद अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने से उन्हें खुशी हुई। वैष्णवी ने किफायती गेंदबाजी की इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ रविवार को यहां खेले गए पहले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और चार ओवर में 16 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। भारत ने इस मैच में आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की। 'विकेट न मिलने से निराश नहीं हूं' वैष्णवी ने मैच के बाद कहा, 'विकेट नहीं मिलने से मैं किसी भी तरह से निराश नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने में सफल रही। अभी चार मैच खेले जाने बाकी हैं।'

ट्रंप ने ग्रीनलैंड में नियुक्त किया विशेष दूत

कोपेनहेगन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सत्ता संभालते ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा जताई थी। अब अमेरिका ने इस दिशा में कदम उठाने की शुरूआत कर दी है। जिस पर डेनमार्क ने चिंता जताई है और बयान जारी कर उनकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी को डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। डेनमार्क के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर को ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त करने का एलान किया है।

ट्रंप, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही थी। अभी ग्रीनलैंड, डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है। खनिज के मामले में समृद्ध ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। बीते मार्च में, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ग्रीनलैंड में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा किया और डेनमार्क पर वहां ध्यान ने देने का आरोप लगाया। हालांकि धीरे-धीरे यह मुद्दा सुर्खियों से गायब हो गया। इस बीच अगस्त में डेनमार्क की सरकार ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े तीन लोगों पर ग्रीनलैंड में गुप्त अभियान चलाने का आरोप लगाया। अब रविवार को, ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। एलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि 'जेफ समझते हैं कि ग्रीनलैंड हमारी और हमारे सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। हम हमारे देश के हितों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।' इस पर लैंड्री ने पर साझा एक पोस्ट में लिखा 'ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए काम करना सम्मान की बात है।' डेनमार्क ने जारी किया बयान इस पर डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, 'यह नियुक्ति ग्रीनलैंड में अमेरिकी हित की निरंतरता की पुष्टि करती है। हालांकि, हम इस बात पर जोर देते हैं कि अमेरिका सहित सभी देशों को डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए।' इस महीने की शुरूआत में, डेनमार्क की रक्षा खुफिया सेवा ने एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा था, 'अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा थोपने और दोस्त और दुश्मन दोनों के खिलाफ सैन्य बल की धमकी देने के लिए कर रहा है'।

हादी के बाद एक और छात्र नेता सिकदर को सिर पर मारी गोली

ढाका। शरिफ उस्मान हादी की मौत के बाद खूलना में एक और छात्र नेता मोतालेब सिकदर को सिर में गोली मारी गई। बढ़ती राजनीतिक हिंसा ने बांग्लादेश में सुरक्षा और चुनावी माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिमी खुलना शहर में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगस्त 2024 में हुए हिंसक छात्र विद्रोह के दूसरे लीडर के सिर में गोली मार दी। यह घटना जाने-माने युवा लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई। एनसीपी की जॉइंट प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर महमूदा मिटू ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा नेशनल सिटिजन पार्टी के खुलना डिवीजन हेड और पार्टी के वर्कर्स फ्रंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद मोतालेब सिकदर को कुछ मिनट पहले गोली मार दी गई। हादी हत्याकांड से जुड़ी कड़ी यह हमला ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश अभी तक युवा नेता शरिफ उस्मान हादी की हत्या से उबर नहीं पाया है। हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। 32 वर्षीय हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वह फरवरी में होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार भी थे। अंतरिम सरकार की प्रतिक्रिया मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हादी की मौत पर देशभर में शोक दिवस मनाया था और हत्यारों को पकड़ने का भरोसा दिया था। हालांकि, नए हमले ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादी की हत्या के बाद ढाका और अन्य बड़े शहरों में दोबारा हिंसक प्रदर्शन देखे गए थे और अब खूलना की यह घटना हालात के और बिगड़ने के संकेत दे रही है। छात्र आंदोलन से बनी पार्टी से जुड़े हैं नेता नेशनल सिटिजन पार्टी की स्थापना इसी साल 28 फरवरी को की गई थी। यह पार्टी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय नागरिक समिति के नेतृत्व में बनी और इसे बांग्लादेश की पहली छात्र-नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी माना जाता है। यह पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अस्तित्व में आई थी।

सऊदी अरब ने आसिम मुनीर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा

इस्लामाबाद/रियाद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर

को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग अब्दुलअजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस' से नवाजा गया है। सऊदी नेतृत्व ने इसे पाकिस्तान-सऊदी अरब के मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान सऊदी अरब ने मुनीर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग अब्दुलअजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया है। मुनीर को यह सम्मान सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने रियाद में दिया है। इसको लेकर सेना ने सोमवार को कहा, 'सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने एक शाही फरमान जारी कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किंग अब्दुलअजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से सम्मानित किया है, जो सऊदी अरब का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है।' इस दौरान सऊदी नेतृत्व ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्यावसायिकता और रणनीतिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। इस सम्मान के जरिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत संबंधों को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। फील्ड मार्शल मुनीर ने इस सम्मान के लिए दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक और सऊदी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, और इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्थायी संबंधों का प्रतीक बताया। इस दौरान मुनीर ने किंगडम की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मुनीर ने किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति, रक्षा और सैन्य सहयोग, रणनीतिक सहयोग और उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियां शामिल हैं।

मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए हथियार बना रहा रूस

पेरिस। नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है, जिसकी मदद से वह पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स को तबाह कर सकेगा। जानिए इसे लेकर पश्चिमी देश क्यों घबराए हुए हैं। नाटो के दो सदस्य देशों की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है, जिससे वह एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बना सके। स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से ही यूक्रेन की सेनाएं युद्धक्षेत्र में संचार करने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर रूस, स्टारलिंक को तबाह कर देता है तो इससे यूक्रेन की संचार व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती है। नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नए हथियार से रूस स्टारलिंक सैटेलाइट पर हजारों छर्रों से हमला कर सकता है, जिससे सैटेलाइट के कई हिस्से क्षतिग्रस्त होकर काम करना बंद सकते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों ने रूस के ऐसे हथियार बनाने पर शक जताया है। स्पेस सिक्योरिटी विशेषज्ञ विक्टोरिया सैमसन का कहना है कि 'मैं नहीं मानती कि रूस ऐसा कोई हथियार बना रहा है, लेकिन रूस अगर ऐसी किसी योजना पर काम कर रहा है तो यह बेहद चौंकाने वाली बात है।'

हालांकि कनाडा सेना की स्पेस डिविजन के कमांडर क्रिस्टोफर हॉर्नर मानते हैं कि रूस ऐसा कर सकता है, लेकिन उनका भी कहना है कि इससे रूस को भी नुकसान हो सकता है। रूस ने अभी तक नाटो खुफिया एजेंसियों के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स से यूक्रेन को मिलती है संचार की सुविधा रूस, एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स को बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि स्टारलिंक की हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात हैं और ये यूक्रेन में संचार में बेहद अहम है। स्टारलिंक यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी नागरिकों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देती है। अगर स्टारलिंक को निशाना बनाया जाता है तो इससे यूक्रेन को खासा नुकसान हो सकता है।

उस्मान हादी की तरह हमलावरों ने सिर में मारी गोली जानें कैसे हमले को दिया गया अंजाम

सिडनी के हमलावर ने पिता से सीखा बंदूक चलाना ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की जांच में खुलासा

ढाका। नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता मोतालेब सिकदर को सोमवार को खुलना में गोली मार दी गई। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमलावरों ने सीधे उनके सिर को निशाना बनाया। यह हमला

सुबह के समय किया गया। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों से पहले देश में हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को बांग्लादेश में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक और छात्र नेता को गोली मार दी। यह घटना शरीफ उस्मान हादी की मौत के कुछ दिनों बाद हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी शहर खुलना में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने 2004 के छात्र आंदोलन के दूसरे नेता मोतालेब सिकदर को गोली मारी है। बांग्लादेशी न्यूज पोर्टल द डेली स्टार के अनुसार, मोतालेब सिकदर को सिर में गोली मारी गई है। सिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। छात्र नेता की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश अभी तक युवा नेता शरिफ उस्मान हादी की हत्या से उबर नहीं पाया है। हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। 32 वर्षीय हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कौन हैं मोतालेब सिकदर? गोलीबारी की घटना के बाद पार्टी द्वारा जारी बयान के अनुसार, मोतालेब सिकदर नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हैं और पार्टी के खुलना डिवीजन के प्रमुख हैं और साथ ही इसके वर्कर्स फ्रंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करते हैं। एनसीपी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, नेशनल सिटिजन पार्टी के खुलना डिवीजन के प्रमुख और पार्टी के वर्कर्स फ्रंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, मोतालेब सिकदर को कुछ मिनट पहले गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 42 साल के सिकदर बांग्लादेश में 2004 के हिंसक छात्र आंदोलन का एक अहम हिस्सा थे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, सिकदर सोनाडांगा के शेखपारा पल्ली के रहने वाले हैं। सोनाडांगा मॉडल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (जांच) मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बदमाशों ने सुबह करीब 11:45 बजे शहर में गाजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास सिकदर के सिर को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोतालेब खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि गोली उनके कान के एक तरफ से घुसी, त्वचा को चीरती हुई दूसरी तरफ से निकल गई। यह हमला पिछले साल छात्र के विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा सिर में गोली मारे जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। किसने घटना को दिया अंजाम? जागोन्यूज24 की खबर के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोतालेब सिकदर अक्सर खुलना गाजी मेडिकल इलाके में अल अक्सा मस्जिद लेन में एक किराए के घर में आता-जाता थे। यह मकान दो महिलाओं ने किराये पर ले रखा था। सिकदर इस मकान में रहने वाली महिला से मिलने जाते थे। हालांकि, महिला का नाम अभी पता नहीं चला है। गोलीबारी की घटना उसी किराए के घर में हुई।

सिडनी के बॉन्डी बीच पर पिछले सप्ताह दो आतंकवादियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी थी। सोमवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सिडनी के बाहर न्यू साउथ वेल्स राज्य के एक इलाके में अपने पिता के साथ बंदूक प्रशिक्षण लिया था। सिडनी के बॉन्डी बीच पर 15 लोगों की हत्या के आरोपी व्यक्ति ने सिडनी के बाहर न्यू साउथ वेल्स राज्य के एक इलाके में अपने पिता के साथ बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया था। सोमवार को जारी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस एक बयान के अनुसार उन लोगों ने सुनियोजित हमले के औचित्य के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह बयान सोमवार को सिडनी के एक अस्पताल से नवीद अकरम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी के बाद सार्वजनिक किया गया, जहां उसकी पेट की चोट का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने 14 दिसंबर की गोलीबारी की घटना स्थल पर अकरम को घायल कर दिया और उसके पिता, 50 वर्षीय साजिद अकरम को मार डाला। अकरम पर 59 अपराधों का आरोप लगा है न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने पुष्टि की कि नवीद अकरम को सोमवार को अस्पताल से जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बयान में आरोप लगाया गया है कि 24 वर्षीय युवक और उसके पिता ने बॉन्डी बीच पर एक वार्षिक यहूदी कार्यक्रम मना रही भीड़ की ओर चार तात्कालिक विस्फोटक उपकरण फेंककर अपना हमला शुरू किया, लेकिन उपकरण फटने में विफल रहे। पुलिस ने इन उपकरणों को तीन एल्युमिनियम पाइप बम और एक टेनिस बॉल बम बताया, जिनमें विस्फोटक, काला पाउडर और स्टील बॉल बियरिंग भरी हुई थीं। इनमें से कोई भी फटा नहीं, लेकिन पुलिस ने इन्हें सक्रिय आईईडी बताया।अधिकारियों ने अकरम पर 59 अपराधों का आरोप लगाया है, जिनमें हत्या के 15 मामले, घायल बचे लोगों के संबंध में हत्या के इरादे से नुकसान पहुंचाने के 40 मामले और एक आतंकवादी कृत्य करने का मामला शामिल है। सरकार ने सोमवार को संसद में हथिहार प्रशिक्षण से संबंधित मसौदा कानून पेश किया आठ दिवसीय हनुक्का उत्सव की शुरूआत में हुआ यह यहूदी विरोधी हमला 1996 में तस्मानिया राज्य में एक अकेले बंदूकधारी द्वारा 35 लोगों की हत्या के बाद से ऑस्ट्रेलिया में हुई सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी की घटना थी। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने सोमवार को संसद में मसौदा कानून पेश किए, जिनके बारे में प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया में सबसे सख्त कानून बन जाएंगे। नए प्रतिबंधों में बंदूक प्रशिक्षण लाइसेंस के लिए पात्रता की शर्त के रूप में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता को अनिवार्य बनाना शामिल होगा। इससे साजिद अकरम, जो स्थायी निवास वीजा धारक भारतीय नागरिक थे, लाइसेंस के दायरे से बाहर हो जाते। साजिद अकरम के पास कानूनी तौर पर छह राइफल और शॉटगन भी थीं। शौकिया निशानेबाजों के लिए नई कानूनी सीमा अधिकतम चार बंदूकें होगी। पुलिस ने कहा कि नवीद अकरम के फोन से मिले एक वीडियो में वह अपने पिता के साथ अपने राजनीतिक और धार्मिक विचारों को दोहराते हुए और बॉन्डी आतंकवादी हमले के लिए अपने औचित्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रहे लोग जायोनिस्टों के कृत्यों की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वह इस्लामिक स्टेट से जुड़ी एक धार्मिक विचारधारा का पालन भी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अक्टूबर में शूट किए गए वीडियो में उन्हें पेड़ों से घिरे घास के मैदान पर शॉटगन से फायरिंग करते और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। पुलिस का आरोप है कि इस बात के सबूत हैं कि आरोपी और उसके पिता ने कई महीनों तक इस आतंकवादी हमले की सुनियोजित योजना बनाई थी।

थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष सुलझाने के लिए आगे आए आसियान देश

कुआलालंपुर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए अब आसियान देशों ने कमर कस ली है। इसी कोशिश के तहत आसियान देशों के विदेश मंत्री कुआलालंपुर में जुटे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष

को सुलझाने के लिए अब आसियान देश आगे आए हैं। मलयेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सोमवार को आसियान देशों के विदेश मंत्री जुटेंगे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में थाईलैंड-कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष को रोकने पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है, जब आसियान देशों के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए आसियान संगठन के देश एक मंच पर आए हैं। ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ संघर्ष विराम टूटा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद है, जिसके चलते दोनों देशों ने बीती जुलाई में एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए थे। जुलाई में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मध्यस्थता करते हुए संघर्ष विराम कराया था। मलयेशिया में हुए आसियान सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में संघर्ष विराम को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि दो हफ्ते पहले यह संघर्ष विराम टूट गया और दोनों देशों ने एक दूसरे पर फिर से हमले शुरू कर दिए। थाईलैंड और कंबोडिया के विदेश मंत्रियों ने की बैठक में शामिल होने की पुष्टि अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को एक बयान जारी कर थाईलैंड और कंबोडिया से दुश्मनी खत्म करने, भारी हथियार हटाने, बारूदी सुरंगें बिछाना बंद करने और कुआलालंपुर शांति समझौते को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान किया। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुंगकेटकेओ ने रविवार को सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और संघर्ष विराम की दिशा में काम करने के थाईलैंड के मजबूत इरादे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड सोमवार को कुआलालंपुर में होने वाली बैठक में भाग लेगा। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि कंबोडिया के विदेश मंत्री प्राक सोखोन बैठक में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, और सभी शांतिपूर्ण तरीकों, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मतभेदों और विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई का नवीनतम दौर 8 दिसंबर को शुरू हुआ, जब सीमा पर झड़प में दो थाई सैनिक घायल हो गए थे।

रूसी जनरल की फिल्मी स्टाइल में हत्या कार के नीचे विस्फोटक लगाकर किया धमाका

मॉस्को। रूस की सेना के एक शीर्ष अधिकारी को फिल्मी स्टाइल में विस्फोट कर मार डाला गया है। हमले का शक यूक्रेन पर है। जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। गौरतलब है कि रूसी सेना के कई अधिकारी इस तरह के हमलों में मारे गए हैं। रूस में एक सैन्य जनरल की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई है। जांचकताओं ने बताया कि सोमवार सुबह दक्षिणी मॉस्को में एक रूसी जनरल की कार के नीचे एक विस्फोटक डिवाइस फटने से उनकी मौत हो गई। रूस की जांच समिति की आधिकारिक प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने बताया कि रूसी सेना के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव की इस हमले में मौत हो गई। पार्किंग में हुआ धमाका रूसी जनरल की हत्या का शक यूक्रेन पर है। पेट्रेंको ने कहा, 'जांचकर्ता हत्या के संबंध में कई कोण से जांच कर रहे हैं। इनमें से एक यह है कि इस घटना को यूक्रेनी खुफिया सेवाओं द्वारा अंजाम दिया गया है।' रूसी मीडिया ने बताया कि मॉस्को की यासेनेवा स्ट्रीट पर एक पार्किंग में सुबह लगभग 7 बजे कार में विस्फोट हुआ। जिसमें रूसी जनरल फानिल सरवारोव की मौत हो गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सरवारोव की हत्या के बारे में जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरवारोव पहले चेचन्या में लड़ चुके थे और सीरिया में मॉस्को के सैन्य अभियान का हिस्सा थे। रूसी सेना के एक और जनरल की भी इसी तरह से हुई थी हत्या गौरतलब है कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने दिसंबर 2024 में एक ऐसे हमले में एक उच्च पदस्थ रूसी जनरल की हत्या की थी। रूसी सेना के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाकर रखे गए बम से मौत हो गई। इस हमले में इगोर के सहायक इल्या पोलिकारपोव की भी मौत हो गई थी। इस मामले में एक उज्बेक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उस पर यूक्रेनी सुरक्षा सेवा की ओर से किरिलोव की हत्या का आरोप लगाया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किरिलोव की हत्या को रूस की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी गलती बताया, और कहा कि उन्हें इससे सीखना चाहिए और अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना चाहिए।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2016/67511 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा दीक्षित प्रिंटिंग प्रेस 120/51/1 मॉडल हाउस लखनऊ से मुद्रित एवं 233जी इंद्रलोक कॉलोनी कृष्ण नगर लखनऊ से प्रकाशित।
E-Mail : mantralko1008@gmail.com । सम्पादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।